साप्ताहिक

सैन समाज सामंजस्य

वर्ष : 1 अंक : 31 जयपुर, सोमवार 2 दिसम्बर, 2024 मूल्यः 1 रूपया

राठौड़ बोले- मुगलों ने हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा, लूट मचाई

अजमेर दरगाह में शिव-मंदिर याचिका पर जंग; दिलावर ने कहा-खुदाई करो, अवशेष मिलेंगे तो निर्णय हो जाएगा

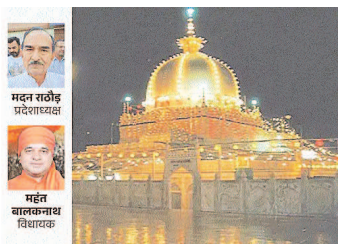

कार्यालय संवाददाता, जयपुर। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे वाली कोर्ट में दायर याचिका के बाद प्रदेश से लेकर पूरे देश में सियासी विवाद छिड़ गया है। राजस्थान के बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सहित कई बीजेपी नेताओं ने मुगल काल में हिंदू मंदिर तोड़ने का दावा करते हुए याचिका का समर्थन किया है। मंत्री मदन मदन दिलावर ने तो खुदाई करवाकर अवशेष मिलने से फैसला होने तक की बात कह दी है। उधर, कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं ने इसे खतरनाक ट्रेंड बताते हुए इसे विभाजनकारी एजेंडे का हिस्सा करार दिया है। दरगाह मुद्दे पर राजस्थान के अलावा राष्ट्रीय नेताओं ने भी तल्ख कमेंट किए हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दरगाह मामले को लेकर बीजेपी आरएसएस और पीएम मोदी पर सवाल उठाए हैं।

पूरा मामला-अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा किया गया है। अजमेर सिविल कोर्ट में लगाई गई याचिका को कोर्ट ने सुनने योग्य मानते हुए सुनवाई की अगली तारीख 20 दिसंबर तय की है। याचिका दायर करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने मुख्य रूप से 3 आधार बताए हैं। विष्णु गुप्ता ने कहा है कि 2 साल की रिसर्च और रिटायर्ड जज हरबिलास शारदा की किताब में दिए गए तथ्यों के आधार पर याचिका दायर की है। किताब में इसका जिक्र है कि यहां ब्राह्मण दंपती रहते थे और दरगाह स्थल पर बने महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना करते थे।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार

कार्यालय संवाददाता, जयपुर, (कासं)। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को फोन पर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने अनूपगढ़ क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। आरोपी हेतराम मंगलाव गांव एक एलएम का निवासी है। एसपी रमेश मौर्य के नेतृत्व में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को उसकी ढाणी से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने प्रदेशाध्यक्ष को फोन करने के बाद अपने मोबाइल को बंद कर दिया था। धमकी देने के लिए जिस सिम का प्रयोग किया गया वह उसके पुत्र के नाम से रजिस्टर्ड है।

मोबाइस सिम ट्रेस करने पर लोकेशन अनूपगढ़ क्षेत्र में मिली : एसपी रमेश मौर्य ने बताया कि गुरुवार को दोपहर करीब 12 बजे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को धमकी भरा कॉल आया था। उच्च स्तर पर मोबाइल नंबर को ट्रेस करने पर पता चला कि सिम कार्ड आशीष कुमार पुत्र हेतराम मंगलाव के नाम पर जारी है। जिसकी लोकेशन अनूपगढ़ क्षेत्र की थी। उच्चाधिकारियों से प्राप्त इस सूचना के आधार पर मोबाइल नंबर ट्रेस करने का प्रयास किया गया। लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ होने के कारण लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाई। इस पर

तुरंत प्रभाव से क्षेत्र में पुलिस टीमें सक्रिय कर दी गई।

आरोपी की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं : उन्होंने बताया कि मोबाइल नंबर के अनुसार धमकी देने वाले शख्स की जानकारी जुटा गई तो सूत्रों से पता चला कि प्रदेश अध्यक्ष को फोन करने वाला हेतराम मंगलाव गांव एक एलएम का निवासी है। गांव एक एलएम में दबिश देकर आशीष कुमार के बारे में जानकारी जुटाई। जानकारी के सामने आया कि जिस नंबर से भाजपा प्रदेशाध्यक्ष को धमकी दी गई उस नंबर को आशीष के पिता हेतराम (50) पुत्र लक्ष्मण राम उपयोग कर रहा हैं। जिसके उसके ढाणी के पास से हिरासत में लिया। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि आरोपी की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं है। एसपी मौर्य ने बताया कि धमकी के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि, पुलिस इसे गंभीरता से लेते हुए आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। सूचना पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मुकेश शर्मा भी इस घटना थाने पहुंचे।

सांसद को जान से मारने की धमकी दी और गाली-गलौज की : दरअसल, शुक्रवार 29 नवंबर को बीजेपी सांसद मदन राठौड़ को एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन पर शख्स ने बीजेपी सांसद को जान से मारने की धमकी दी और गाली-गलौज की। इस घटना के बाद बीजेपी सांसद मदन राठौड़ ने पुलिस अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी। मदन राठौड़ ने कहा कि मुझे फोन पर कहा गया कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, क्या इसीलिए मुझे राज्यसभा भेजा गया है? जबकि मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या परेशानी है, किस विषय पर बात करना चाहते हो, लेकिन वो शख्स मुझे गाली-गलौज करता रहा।

कोर्ट ने लगाई रोक; गवर्नमेंट का जवाब- सरकारी संपत्ति है, नोखा नगरपालिका का कोई संबंध नहीं

कार्यालय संवाददाता, जयपुर। दिल्ली की पटियाला हाउस की कॉमर्शियल कोर्ट-2 ने इंडिया गेट के पास स्थित बीकानेर हाउस के कुर्की आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह रोक राज्य सरकार की रिकॉल एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए लगाई। सरकार की ओर से पैरवी करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने कहा- बीकानेर हाउस राज्य सरकार की संपत्ति है। जबकि मामला नोखा नगरपालिका के खिलाफ है। उसका बीकानेर हाउस से कोई संबंध नहीं है। डिक्री होल्डर मैसर्स एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड ने शपथ पत्र में बीकानेर हाउस के स्वामित्व का गलत दावा पेश किया है। उन्होंने बीकानेर हाउस से संबंधित सरकारी रिकॉर्ड भी कोर्ट मे पेश किया।

बीकानेर हाउस की नहीं हो सकती कुर्की : सरकार की ओर से कहा गया- सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 60 के तहत बीकानेर हाउस कुर्की से मुक्त है। यह एक सरकारी संपत्ति है। इसका उपयोग सार्वजनिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाता है।

बीकानेर हाउस में राजस्थान के मुख्यमंत्री का कार्यालय, राजस्थान हाईकोर्ट रजिस्ट्री और अतिरिक्त महाधिवक्ता सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्यालय संचालित होते हैं। ऐसी महत्वपूर्ण संपत्ति की कुर्की से सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी। वहीं, कोर्ट ने कुर्की का एकतरफा आदेश दिया था। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन है।

7 दिन में पैसा जमा करा देंगे

आज सुनवाई के दौरान नोखा नगर पालिका की ओर से भी कहा गया कि बीकानेर हाउस उनकी संपत्ति नहीं है। उन्होंने कोर्ट को आश्वासन दिया कि डिक्री राशि को सात दिनों के भीतर अदालत में जमा कर दिया जाएगा। कंपनी के पक्ष में पास अवॉर्ड को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। इस पर कोर्ट ने कुर्की आदेश पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई के लिए 7 जनवरी 2025 की तारीख तय की है।

यह था मामला

नोखा नगर पालिका और मैसर्स एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच विवाद होने पर मध्यस्थता हुई। इसमें मीडिएटर ने कंपनी के पक्ष में 50.57 लाख का भुगतान करने के लिए कहा। नोखा नगर पालिका ने न तो कंपनी को राशि का भुगतान किया और न ही इस आदेश को चुनौती दी। इसके बाद कंपनी ने नवंबर 2023 में नोखा नगर पालिका के खिलाफ दिल्ली की कॉमर्शियल कोर्ट में याचिका दायर कर दी। इस पर सुनवाई के दौरान नोखा नगर पालिका की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने 18 सितंबर 2024 को बीकानेर हाउस की कुर्की के आदेश जारी कर दिए।

गहलोत बोले-800 साल पुरानी अजमेर दरगाह पर कोर्ट केस गलत

पीएम मोदी यहां चादर चढ़ा चुके, उन्हीं की पार्टी के लोग केस कर रहे हैं

कार्यालय संवाददाता, जयपुर। राजस्थान के पूर्व ष्टरू अशोक गहलोत ने अजमेर दरगाह परिसर में शिव मंदिर होने के दावे से उठे विवाद को लेकर BJP, RSS और PM नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने कहा- 15 अगस्त 1947 तक बने जो भी धार्मिक स्थान जिस स्थिति में हैं, वे उसी में रहेंगे, यह कानून बना हुआ है।

उन पर सवाल उठाना गलत है। गहलोत ने ये भी कहा- अजमेर दरगाह 800 साल पुरानी है। दुनियाभर से लोग यहां आते हैं। दुनिया के मुल्कों के मुस्लिम भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं। प्रधानमंत्री कोई भी हो, कांग्रेस, BJP या किसी दल के हों, पंडित नेहरू के जमाने से मोदी जी तक तमाम प्रधानमंत्री की तरफ से दरगाह में चादर चढ़ती है।

चादर चढ़ाने के अपने मायने होते हैं। आप चादर भी चढ़ा रहे हैं और आपकी पार्टी के लोग कोर्ट में केस भी कर रहे हैं। आप भ्रम पैदा कर रहे हैं तो लोग क्या सोच रहे होंगे? जहां अशांति है वहां विकास नहीं हो सकता, वहां विकास ठप हो जाता है। ये बात किसको कहनी चाहिए, ये बातें मोदी जी और RSS को करनी चाहिए। देश अभी

वो चला रहे हैं।

15 अगस्त, 1947 तक बने धर्मस्थलों पर सवाल उठाना गलत : पूर्व CM ने कहा- जहां तक मुझे जानकारी है, धार्मिक स्थान किसी भी धर्म के हों, 15 अगस्त 1947 तक जो बने हुए हैं, उस पर सवाल नहीं होना चाहिए, इसका कानून बना हुआ है। जब से RSS, BJP सरकार आई है, आप देख रहे हो, देश में धर्म के नाम पर राजनीति चल रही है। चुनाव चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे पार्लियामेंट का हो, सारे चुनाव ध्रुवीकरण के आधार पर जीते जा रहे हैं। खुलकर धर्म के आधार पर ये लोग टिकट बांट रहे हैं। देश में स्थिति तो बड़ी विकट है। यह स्थिति आसान नहीं है। यह तो इनको खुद को देखने की बात है, जो आज शासन में हैं।

'पक्ष और विपक्ष में बढ़ गई दूरियां'

गहलोत ने कहा- शासनकर्ता की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। सत्ता में जो हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि विपक्ष को साथ लेकर चलें, विपक्ष की भावना का आदर करें, जो कि ये नहीं कर रहे हैं। पक्ष और विपक्ष में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, वह अपनी जगह है। पूर्व CM बोले- जब 15 अगस्त 1947 की स्थिति में संसद में कानून पास हो गया, उसके बावजूद मंदिर दरगाह में क्या था, पहले क्या था उसी में फंसे रहेंगे तो देश के मूल मुद्दों का क्या होगा? मूल मुद्दे क्या हैं, यह ज्यादा महत्व रखता है? महंगाई, बेरोजगारी, विकास का मुद्दा है, अर्थव्यवस्था का है, सामाजिक न्याय और सामाजिक व्यवस्थाओं का मुद्दा है।

मोदी और RSS को छुआछूत मिटाने का अभियान चलाना चाहिए

गहलोत ने कहा- RSS कहता है कि हम सांस्कृतिक संगठन हैं। हिंदुओं की रक्षा करते हैं। सब जातियों को साथ लेकर चलते हैं। हिंदू चाहे वह दलित वर्ग के हों, चाहे OBC के हों, चाहे कोई कास्ट के हों, सब हिंदू हैं। ऋस्- को छुआछूत, भेदभाव को मिटाने के लिए अभियान चलाना चाहिए।

जब मोदी कहते हैं कि मैं थाली और ताली बजवा सकता हूं। कुछ भी कर सकता हूं और देश उनकी बात सुनता है तो सबसे पहले काम उनको यही करना चाहिए था। एक तारीख देनी चाहिए थी कि इस तारीख के बाद में कोई छुआछूत नहीं होगा। सब एक समान हैं, यह होना चाहिए था। यह बात ये करते नहीं हैं।

ट्रायल कोर्ट से कहा- 8 जनवरी तक केस में कोई एक्शन न लें

सुप्रीम कोर्ट का आदेश-संभल मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी, शांति जरूरी

कार्यालय संवाददाता, संभल (एजेंसी)। संभल की जामा मस्जिद मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आदेश दिया कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि 8 जनवरी तक केस में कोई एक्शन न लें। शांति जरूरी है। संभल में रविवार, 24 नवंबर को मस्जिद में सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में 4 युवकों की मौत हुई थी। संभल की चंदौसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर 19 नवंबर को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करते हुए सर्वे का आदेश दिया था। हिंदू पक्ष का दावा है कि जामा मस्जिद हरिहर मंदिर है। गुरुवार को संभल की शाही जामा मस्जिद की तरफ से सुप्रीम

कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। ष्टछ्ढ की बेंच में इस पर सुनवाई हुई।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 6 पॉइंट्स...

1- मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट सील रखी जाएगी। इसे खोला नहीं जाएगा।

2- CJI ने कहा- मामले में सही और गलत क्या है। हम अभी यह नहीं देख रहे हैं। याचिकाकर्ताओं को आदेश को चुनौती देने का अधिकार है।

3- CJI ने कहा- हम इस समय कुछ नहीं कहना चाहते। हम इसे पेंडिंग रखेंगे। यह सुनिश्चित करें कि शांति बनी रहे।

4- हाईकोर्ट की अनुमति के बिना मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ट्रायल कोर्ट 8 जनवरी तक कोई फैसला नहीं सुनाए।

5- इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि मुस्लिम पक्ष की याचिका फाइल होते ही इस पर 3 दिन के भीतर सुनवाई करें।

6- सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखें। दोनों समुदायों में शांति समिति का गठन करें।

विष्णु शंकर जैन ने कहा-कोर्ट ने कहा कि मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट जा सकती है

अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया- सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले चिंता जताई की वहां पर शांति और सद्भाव बरकरार रहे। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी से कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। सुप्रीम ने ये भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हैं तो मामला हाई कोर्ट में लिस्ट किया जाए और हाई कोर्ट के अगले निर्देश का इंतजार किया जाए। तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रुकी रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा-संभल मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी

संभल मामले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी। इसके अलावा, ट्रायल कोर्ट यानी चंदौसी की सिविल कोर्ट को निर्देश दिया कि 8 जनवरी तक इस केस में कोई भी एक्शन मत लीजिए।

शांति जरूरी है। दरअसल, गुरुवार को संभल मस्जिद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इसमें 3 मांग की गई थी।

शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा के घर-ऑफिस पर ईडी का छापा

पोर्नोग्राफी मामले में एक्शन, एक्ट्रेस के पति 2021 में इसी केस में गिरफ्तार हुए थे

मुंबई (एजेंसी)। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के घर पोर्नोग्राफी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार सुबह छापामारी की। घर के बाद राज कुंद्रा के दफ्तर में भी छापा मारा गया है। इसके अलावा मुंबई और उत्तर प्रदेश में करीब 15 जगहों की

तलाशी ली जा रही है। इसके जरिए श्वष्ठ मोबाइल एप्लिकेशन और दूसरे माध्यमों से पोर्नोग्राफी के सर्कुलेशन का पता लगा रही है। राज कुंद्रा पर आरोप हैं कि वो एप हॉटशॉट के जरिए पोर्न कंटेंट लोगों तक पहुंचाते हैं और इसका प्रोडक्शन भी करते हैं। इस एप के मालिक राज कुंद्रा हैं। उनकी ये एप पहले गूगल और एप्पल में उपलब्ध थी, हालांकि 2021 में उनके खिलाफ केस होने के बाद इसे हटा दिया गया था।

पुलिस कैसे पहुंची? : फरवरी 2021 में मड आईलेंड में पुलिस ने छापा मारा और पोर्न रैकेट का भंडाफोड़ किया। इस केस में टीवी एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ का नाम सामने आया। पुलिस को गहना से राज कुंद्रा की कंपनी विहान इंटरप्राइज में काम कर रहे उमेश कामत के बारे में पता चला।

उमेश राज कुंद्रा के लंदन स्थित बहनोई प्रदीप बख्शी को सारे वीडियो एक शेयरिंग एप्लिकेशन से भेजता था। प्रदीप कंपनी केनरीन के ऐप पर सारे वीडियो अपलोड करता था। उमेश यह ट्रांसफर राज के ऑफिस से ही करता था। चार्जशीट के मुताबिक, उमेश के मोबाइल से 'हॉटशॉट' ऐप का अकाउंट और 'हॉटशॉट' टेकन डाउन नाम के दो वॉट्सऐप ग्रुप के बारे में पता चला। इन दोनों ग्रुप का एडमिन भी राज ही था।

राज और उसकी कंपनी के आईटी हेड रयान थारप, उमेश, प्रदीप बख्शी और दूसरे कर्मचारियों के बीच %हॉटशॉट% और 'बोली फेम' ऐप के कंटेंट पर काम करने वालों को पेमेंट, गूगल और एपल की तरफ से पेमेंट, यूजर्स रेवेन्यू के बारे में वॉट्सऐप ग्रुप में चैट हुई थी, मेल भेजे गए थे। आय का ब्योरा आदि स्टोर किया गया था।

यह सब हाथ लगने से पता चला कि राज ही सारे रैकेट का मास्टरमाइंड है, वह प्रदीप बख्शी के जरिए अश्लील वीडियोज अपलोड करवाता था और उसके बदले में पैसा कमाता था।

बाड़मेर में बीएसएफ के जवान ने खुद को मारी गोली

गले पर राइफल रखकर किया सुसाइड, मौके पर ही मौत

कार्यालय संवाददाता, बाड़मेर भारत-पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) जवान ने ड्यूटी पर जाने से पहले शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे अपनी राइफल से गोली मारकर सुसाइड कर लिया। गोली की आवाज सुनकर वहां पर मौजूद अन्य जवान दौड़कर पहुंचे और देखा तो जवान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उन्होंने घटना की जानकारी बीएसएफ के अधिकारियों को दी। इसके बाद सूचना देने पर करीब 10 बजे बाखासर पुलिस मौके पर पहुंची। घटना बाड़मेर जिले के बाखासर जाटों का बेरा (छ्यक्क) चैक पोस्ट की है। मौके पर चौहटन डीएसपी जीवनलाल, बाखासर थानाधिकारी विशन सिंह मय पुलिस जाब्ता मौका मुआयना कर रहे है। वहीं, पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाया है।

सुसाइड के कारणों की जांच में जुटी पुलिस

जानकारी के अनुसार नीमकाथाना निवासी शंकरलाल गुर्जर (52) बाड़मेर जिले में बीएसएफ की 83 बटालियन में हेड कॉन्स्टेबल पद पर तैनात था। शुक्रवार को सुबह इंडो-पाक इंटरनेशनल बॉर्डर की तारबंदी के पास ड्यूटी करने के लिए तैयार हो रहा था। सुबह करीब 7 बजे चैक पोस्ट पर तैयार होने के दौरान अपनी राइफल से गले से ऊपर ठोड़ी के नीचे गोली मारकर सुसाइड कर लिया। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस मौके की कार्रवाई कर रही है। वहीं सबूत जुटाने के लिए एफएसएल टीम को बुलाया है। इसके बाद बॉडी को हॉस्पिटल की मॉर्च्युरी में शिफ्ट करवाया जाएगा। सुसाइड के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है और जांच जारी है। जवान के परिवार को सूचना दी गई है।

अकेली पड़ती कांग्रेस, अदाणी मुद्दे पर ममता बनर्जी का किनारा

राहुल गांधी को यह लगता है कि अदाणी समूह दागदार है तो वह अपनी सरकारों को उससे कोई नाता न रखने के लिए क्यों नहीं कह पा रहे हैं? यह समझना भी कठिन है कि कांग्रेस अमेरिकी अदालत के आकलन को अंतिम सत्य की तरह क्यों ले रही है और वह भी तब जब उसने रिश्वत के कथित लेन-देन के कोई प्रमाण नहीं पेश किए हैं?

संसद में एक और दिन अदाणी प्रकरण के साथ कुछ अन्य मामलों को लेकर हंगामा हुआ और फिर वह दिन भर होता ही रहा। इस पर आश्चर्य नहीं कि हंगामा करने में कांग्रेस सबसे आगे रही। वह और विशेष रूप से उसके नेता राहुल गांधी न जाने कब से अदाणी समूह को कोस रहे हैं। एक अमेरिकी अदालत के फैसले के बाद वह हाथ धोकर इस समूह के पीछे पड़ गए हैं, लेकिन शायद वह यह देखने से इन्कार कर रहे हैं कि आइएनडीआइए के सभी घटक कांग्रेस के रवैये से सहमत नहीं। ममता बनर्जी ने जिस तरह यह कहा कि उनका दल कांग्रेस की ओर से उठाए गए किसी एक मुद्दे को प्राथमिकता नहीं देगा, उससे यही संकेत मिला कि वह नहीं चाहतीं कि अदाणी मामले को तूल दिया जाए। तृणमूल कांग्रेस के इस रवैये का कारण कुछ भी हो, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इसी साल जून में अदाणी समूह को कोलकाता बंदरगाह के रखरखाव और संचालन का अनुबंध मिला था। कांग्रेस को इसकी भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि गत दिवस ही माकपा के नेतृत्व वाली केरल सरकार ने बंदरगाह के विकास के लिए अदाणी समूह के साथ एक पूरक समझौते को अंतिम रूप दिया।

साफ है कि माकपा भी अदाणी मामले में कांग्रेस के रुख से सहमत नहीं। इस तथ्य को भी ओझल नहीं किया जाना चाहिए कि तेलंगाना सरकार ने अदाणी समूह के साथ एक समझौता कर रखा है और अतीत में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने भी राज्य में इस समूह के निवेश को हरी झंडी दी थी। यदि राहुल गांधी को यह लगता है कि अदाणी समूह दागदार है तो वह अपनी सरकारों को उससे कोई नाता न रखने के लिए क्यों नहीं कह पा रहे हैं? यह समझना भी कठिन है कि कांग्रेस अमेरिकी अदालत के आकलन को अंतिम सत्य की तरह क्यों ले रही है और वह भी तब, जब उसने रिश्वत के कथित लेन-देन के कोई प्रमाण नहीं पेश किए हैं? इससे इन्कार नहीं कि अमेरिकी अदालत की कार्रवाई से जो सवाल उठे हैं, उनके जवाब सामने आने चाहिए, लेकिन इसका भी कोई मतलब नहीं कि जैसा राहुल गांधी चाह रहे हैं, वैसा हो।

वह चाह रहे हैं कि अदाणी समूह के प्रमुख गौतम अदाणी की तुंरत गिरफ्तारी हो। क्या यह विचित्र नहीं कि यह चाहत उन राहुल गांधी की है, जो खुद नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर चल रहे हैं? यह भी विचित्र है कि संयुक्त अरब अमीरात, तंजानिया और श्रीलंका तो अदाणी समूह पर अमेरिकी अदालत की टिप्पणी को महत्व नहीं दे रहे हैं, लेकिन भारत में कांग्रेस के नेता और कुछ अन्य लोग उसे बिनी किसी जांच-पड़ताल दंडित करने को उतावले हैं।

यह उतावलापन इसलिए भी ठीक नहीं, क्योंकि निवेशक अदाणी समूह पर भरोसा जता रहे हैं और इसी कारण उसके शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है।

विधायक गोपाल शर्मा की मांग पर गृह राज्य मंत्री ने डीजीपी को लिखा नोट

जयपुर (कासं)। राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा बनाई जा रही नई बाउंड्री के संबंध में सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने गुरुवार को गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म से मुलाकात की और उन्हें क्षेत्रवासियों की चिंताओं से अवगत कराया। साथ ही निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की। विधायक शर्मा की मांग पर मंत्री बेढ़म ने डीजीपी यूआर साहू को मामले की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। विधायक शर्मा ने गुरुवार को बेढ़म से मुलाकात की और उन्हें जयपुर नगर निगम हैरिटेज के वार्ड-32 की जेपी कॉलोनी के सेक्टर- 1 और तुलसी नगर में आरपीए द्वारा किए जा रहे नए निर्माण

को लेकर स्थानीय निवासियों की चिंताओं से अवगत करवाया। शर्मा ने बताया कि आरपीए द्वारा पहले की बनी हुई बाउंड्री को हटाकर परिसर का विस्तार करते हुए नई बाउंड्री का निर्माण किया जा रहा है। इससे लगभग 50 वर्षों से निवास कर रहे लोगों के सामने तत्काल विस्थापन का गंभीर संकट आ गया है। शर्मा ने कहा कि पट्टाधारक मकानों पर निशान लगाकर तोड़ने की धमकी दी जा रही है। साथ ही, द्रव्यवती नदी के मूल क्षेत्र में अतिक्रमण कर उसे छोटे नाले का स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है। क्षेत्रवासियों के ज्ञापन और दस्तावेज देखने के बाद गृह राज्य मंत्री ने डीजीपी यूआर साहू को नोट लिखकर प्रकरण की पूरी जांच करवाने और रिपोर्ट लेकर विधि सम्मत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस पर विधायक शर्मा ने क्षेत्रवासियों की ओर से मंत्री का आभार जताया।

आरटीएस का आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम

लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को जन–जन तक पहुंचाने में महती भूमिका निभायें अधिकारी : हेमंत मीणा

कार्यालय संवाददाता, जयपुर (कासं)।राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि प्रदेश में हर तबके तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार अति संवेदनशील होकर कार्य कर रही है। उन्होंने प्रशासनिक वर्ग का आह्वान किया कि वह लोक हितैषी निर्णय एवं कार्यक्रमों को जन–जन तक पहुंचाने में अपनी महती भूमिका अदा करें। वे गुरुवार को अजमेर के आरआरटीआई सभागार में आरटीएस के 31वें बैच के तहत आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे आरटीएस प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिकारी वर्ग अपने कार्य क्षेत्र में संवेदनशीलता, कर्त०?यनिष्ठा, ईमानदारी एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि वे सदैव गरीबों को गणेश मानकर कार्य करेंगे तो उन्हें हर क्षेत्र में सफलता अर्जित होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की सेवाओं का लाभ त्वरित एवं पारदर्शी ढंग से आम जनता पहुंचाने के उद्देश्य से ई फाइल सिस्टम को प्रभावी बनाया गया है। आम जन के अभाव अभियोगों के निराकरण के लिए सरकार हर संभव राहतकारी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कृषक वर्ग की समस्याओं के त्वरित निराकरण के भी प्रयास किया जा रहे हैं। कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाने के लिए लोक जागरूकता के भी प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।

कार्यक्रम में राजस्व मंडल अध्यक्ष श्री हेमंत कुमार गेरा ने प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रशिक्षण उपरांत बेहतरीन लोकसेवाएं प्रदान करने के लिए शुभकामनाएं दी। निबंधक श्री महावीर प्रसाद ने प्रशिक्षण की बारीकियों एवं बेहतरीन अनुभवों का लाभ भावी कार्य क्षेत्र में जन–जन तक पहुंचाने की बात कही। कार्यक्रम का संयोजन गिरिराज सिंह राणावत ने किया जबकि आरआरटीआई की कार्यवाहक निदेशक कोमल चौधरी ने आभार जताया।

ऑपरेशन कवच 4.0 : जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देश पर कार्रवाई को दिया अंजाम

82 से अधिक वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई, 7 लाख से अधिक का राजस्व वसूला

कार्यालय संवाददाता, जयपुर (कासं)। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देश पर कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (प्रथम) की टीम ने ऑपरेशन कवच 4.0 के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (प्रथम) राजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि प्रवर्तन दलों ने विशेष सघन अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए कुल 82 चालान बनाएं एवं चालान राशि के तौर पर 7 लाख से अधिक का राजस्व वसूल किया, साथ ही 1 लाख 25 हजार की राशि सीएफ के रूप में प्राप्त हुए। उन्होंने बताया कि सघन जांच अभियान ऑपरेशन कवच के तहत ओवरलोड, ओवर क्राउड, ओवर प्रोजेक्टेड वाहनों के साथ–साथ रश ड्राइविंग, ड्राइविंग के समय मोबाइल का उपयोग, बिना हेलमेट, बिना फिटनेस, बिना पीयूसी जैसे वाहन चालको के खिलाफ नियमानुसार प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है। वहीं, नियम विरुद्ध संचालित वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस एवं पंजीयन निलम्बन की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जा रही है।

संसदीय कार्य मंत्री ने जोधपुर के गंगाणा विद्यालय में 19.86 लाख की लागत से निर्मित कक्षा-कक्ष का किया लोकार्पण

प्रदेश सरकार शैक्षणिक उन्नयन एवं अवसंरचना विकास के कृत संकल्प : संसदीय कार्य मंत्री

कार्यालय संवाददाता, जयपुर (कासं)। संसदीय कार्य,विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर जिले की ग्राम पंचायत गंगाणा की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मध्य पूर्व पुलिस चौकी में गुरुवार को 19.86 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित कक्षा–कक्ष का विधिवत् रूप से फीता काटकर लोकार्पण किया।

संसदीय कार्य मंत्री पटेल ने कहा माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शैक्षणिक उन्नयन एवं विद्यालयों में अवसंरचना विकास के कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कक्षा–कक्ष, लैब, पुस्तकालय एवं शौचालय निर्माण के लिए इस बजट में 350 करोड़ रुपए और प्रदेश के 750 विद्यालयों के भवनों की मरम्मत के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।

मेधावी विद्यार्थियों के प्रोत्साहन के लिए सरकार दे रही निःशुल्क टैबलेट्स

पटेल ने कहा बजट में राज्य में सभी वर्गों के राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों में आवासित छात्र–छात्राओं को देय मैस भत्ता 2 हजार 500 रुपए से बढ़ाकर 3 हजार रुपए प्रतिमाह किया गया है। उन्होंने कहा राजकीय विद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन के लिए प्रोत्साहन देने के लिए 8 वीं,10 वीं एवं 12 वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में राज्य तथा जिला स्तरीय मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों को तीन वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ टैबलेट्स निःशुल्क दिए जा रहे है।

कक्षा-कक्ष निर्माण के लिए 11 लाख रुपए की घोषणा

पटेल ने कहा विद्यालय भारत के भविष्य निर्माण के केंद्र है। उन्होंने कहा शिक्षक राष्ट्र निर्माण में सबसे महत्ती भूमिका निभाते है। संसदीय कार्य मंत्री ने विद्यालय में कक्षा–कक्ष निर्माण के लिए 11 लाख रुपए की घोषणा की।

दोहरे आवेदन एवं डमी कैंडिडेट पर लगेगी आधार सत्यापन से लगाम

कार्मिक विभाग ने भी दिया आयोग को अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक सत्यापन का अधिकार

कार्यालय संवाददाता, जयपुर (कासं)।राजस्थान लोकसेवा आयोग को राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग से भी अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक सत्यापन की अनुमति प्राप्त हो गई है। 27 नवंबर 2024 को जारी की गई अधिसूचना अनुसार आयोग अभ्यर्थियों के द्वारा किए जाने वाले दोहरे आवेदनों की छंटनी, अभ्यर्थियों के सत्यापन, जालसाजी एवं डमी कैंडिडेट की रोकथाम के लिए आधार सत्यापन प्रणाली का उपयोग कर सकेगा। इससे पूर्व माह सितंबर 2024 में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भी आधार कार्ड के माध्यम से अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन करने की अनुमति आयोग को प्राप्त हो गई थी।

आयोग सचिव ने बताया कि आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों यथा– ऑनलाइन आवेदन जांच, साक्षात्कार, काउंसलिंग, दस्तावेज सत्यापन, लिखित परीक्षा व नियुक्ति में अभ्यर्थी की पहचान का सत्यापन इसके माध्यम से किया जा सकेगा। गत् समय के दौरान सामने आए डमी अभ्यर्थियों के प्रकरणों को देखते हुए आधार बायोमैट्रिक सत्यापन आयोग की विश्वसनीयता तथा कार्य प्रणाली में मील का पत्थर सिद्ध होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के आग्रह पर कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा 8 मई 2024 को इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार को पत्र प्रेषित किया गया था। इस पर कार्यवाही करते हुए आधार एक्ट 2016 की धारा 4 एवं आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस नियम 2020 के अंतर्गत अभ्यर्थियों की पहचान सत्यापित करने के उद्देश्य से आधार सत्यापन का लिंक प्रदान किया गया था। इसी क्रम में राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा भी आयोग को इसका उपयोग करने की अनुमति के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह आयोग की कार्यप्रणाली तथा भर्ती परीक्षाओं की शुचिता में वृद्धि के दृष्टिगत महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षाओं की शुचिता भंग करने तथा जालसाजी करने वाले व्यक्तियों व नकल गिरोहों पर लगाम के लिए आवेदन से लेकर परीक्षा प्रक्रियाओं तक में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इनमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान अंगूठा निशानी, लाइव फोटो कैप्चर, ओएमआर शीट में पांचवा विकल्प, इंटरव्यू में बोर्ड आवंटन जैसी विशेष प्रक्रियाएं सम्मिलित है। आधार बायोमेट्रिक सत्यापन सुविधा प्राप्त होने से आयोग अब और अधिक सशक्त हो सकेगा तथा जालसाजी कर परीक्षाओं में सम्मिलित होने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी। आयोग द्वारा प्रक्रिया के संचालन हेतु बुनियादी संसाधन जुटा लिए गए हैं एवं शीघ्र ही चरणबद्ध रूप से अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक सत्यापन व्यवस्था आयोग द्वारा प्रारंभ की जाएगी।

जलदाय विभाग के अधिकारियों ने शीघ्र समस्या का दिया आश्वासन

कार्यालय संवाददाता, जयपुर (कासं)।

सीकर शहर के वार्ड नंबर 41 में पिछले लंबे समय से चल रही पानी की समस्या को लेकर आज क्षेत्र के लोगों ने जलदाय विभाग पहुंचकर प्रदर्शन किया तथा अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया वार्ड नंबर 41 के गोगामेडी क्षेत्र और ख़ातियो की गली मैं पिछले लंबे समय से पानी की समस्या बनी हुई है समस्या को लेकर कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया लेकिन निदान नहीं हुआ हालांकि एक बार जलदाय विभाग के सहायक अभियंता ने मौके पर पहुंचकर समस्या का जायजा भी लिया था लेकिन निदान नहीं हो सका क्षेत्र के लोगों ने जलदाय विभाग पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए शीघ्र समस्या के निदान की मांग रखी जलदाय विभाग के सहायक अभियंता प्रमोद कुमार ने समस्या को गंभीरता से लेते हुए जल सप्लाई को दुरुस्त करने सहित क्षेत्र में अति शीघ्र इलाके में ट्यूबवेल लगाने का आश्वासन दिया हम आपको बता दें कि वार्ड नंबर 41 के कई क्षेत्रों में गर्मी से लेकर अभी तक पानी की भयंकर समस्या बनी हुई है।

जबकि सर्दी दस्तक दे चुकी है लेकिन समस्या यथावत बनी हुई है जिसके चलते लोगों में जलदाय विभाग के प्रति गहरा आक्रोश है प्रदर्शन के बाद विभाग के अधिकारियों द्वारा मिले आश्वासन के बाद अब क्षेत्र के लोग समस्या निदान की आस लगाए बैठे हैं।

अगर फिर भी जल सप्लाई सुचारू नहीं हुई तो क्षेत्र के लोग दोबारा जलदाय विभाग पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के नेता आनंद सिंह कच्छावा, बजरंग सिंह चंदेल, जितेंद्र सिंह चंपावत, झाबर सिंह गहलोत, चेतन परिहार, किशन सिंह पवार, विनोद सिंह दईया, पप्पू सिंह परिहार, महेंद्र सिंह चौहान, रवि चौहान, विक्रम सिंह परिहार, सीताराम दहिया, त्रिलोक सिंह, विक्रम सिंह शेखावत, जितेंद्र सिंह बडगूजर, उमेश कटारिया, मिथुन सिंह, सरवन देवी, सुमन गहलोत, गुड्डी शर्मा, मीरा जांगिड़, सुशीला गहलोत, ग्यारसी जांगिड़, उत्सव पडियार, गीता चौहान सहित काफी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष मौजूद रहे।

संपादकीय

संभल हिंसा से सुलगते सवालों का जवाब आखिर कौन देगा?

कहते हैं कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा भुगती। भारत देश और भारतीय इसका जीता-जागता उदाहरण हैं। मुहम्मद बिन कासिम जैसे मुस्लिम आक्रांताओं और उनके अनुगामियों ने तलवार की नोंक पर भारत की देशज सत्ता हथियाने के बाद यहां की सनातन सभ्यता-संस्कृति के साथ जो खिलवाड़ किया, उसका हिसाब-किताब अब उनकी धर्मांतरित पीढ़ियों को देना पड़ रहा है। खासकर मंदिरों को ढहाकर जिन मस्जिदों का निर्माण किया गया, उनकी मुक्ति यानी जीर्णोद्धार का अभियान अब स्थानीय प्रशासन के गले की हड्डी बन चुकी है। देखा जाए तो ऐसे मामलों में कभी आपसी विवाद, तो कभी न्यायिक आदेश के अनुपालन में सिविल व पुलिस प्रशासन को अपनी सक्रियता दिखानी पड़ती है, लेकिन कानून का राज स्थापित करने में उनकी विफलता से जब तब सांप्रदायिक दंगे भी भड़क जाते हैं जिससे धन-जन की भारी क्षति भी होती है। अतीत की बात यदि भुला दी जाए तो भी स्वतंत्र भारत की यह एक बड़ी चुनौती है, जबकि यह हिंदुओं के हिस्से का हिंदुस्तान है, क्योंकि मुस्लिमों को तो पाकिस्तान दे ही दिया गया, जिसका भाग ही बंगलादेश है। लेकिन भारत को हिन्दू राष्ट्र घोषित करने के बजाय धर्मनिरपेक्ष देश घोषित करना, फिर वोट बैंक की राजनीति के तहत मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति अपनाना और आतंकवाद पर समझौतापरस्त रुख अपनाने की प्रतिक्रियाओं में उभरे राष्ट्रवाद व हिंदुत्व की जनभावना ने जब बदले की कार्रवाई शुरू की तो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष ताकतों में खलबली मच गई। रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद और उसके न्यायसंगत समाधान ने तथाकथित धर्मनिरपेक्ष नेताओं के सत्ता की चूलें हिला दीं और हर ओर उनका पतन हुआ। अब रामजन्मभूमि मुक्ति मिशन के पूरा होने के बाद न केवल मथुरा-काशी, बल्कि वैसे तमाम मंदिरों की मुक्ति के सवाल जनमानस में सुलगने लगे हैं, जिन्हें बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के बाद मस्जिदों में तब्दील कर दिया गया था। चूंकि इतिहास खुद को दुहराता है, इसलिए अब धीरे-धीरे पुराने गड़े मुर्दे उखड़ने लगे हैं, उखाड़े जाने लगे हैं। इसी कड़ी में उत्तरप्रदेश के संभल जनपद के सदर तहसील स्थित दीपा सराय की जामा मस्जिद को जब हिंदू पक्ष श्री हरिहर मंदिर होने का दावा कर रहे हैं और उनके इसी दावे के आधार पर कोर्ट ने जब मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दिया था, तो फिर कानून के अनुपालन में कार्य कर रहे लोगों के विरुद्ध शांतिप्रिय समुदाय द्वारा बवाल काटने को न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि संभल के कैला देवी मंदिर के ऋषिराज गिरी समेत आठ वादियों ने सिविल जज सीनियर डिविजन आदित्य कुमार सिंह की चंदौसी स्थित कोर्ट में इस बाबत एक वाद दाखिल किया है। जिसके दृष्टिगत कोर्ट ने कमिशन गठित कर रिपोर्ट मांगी है। इस मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर 2024 को होगी। हिंदू पक्ष के एक स्थानीय वकील गोपाल शर्मा ने बताया है कि, कोर्ट में दायर याचिका में बताया गया है कि बाबरनामा और आइन- ए-अकबरी ने पुष्टि की है कि उस स्थान पर हरिहर मंदिर था। मंदिर को मुगल सम्राट बाबर ने 1529 में ध्वस्त कर दिया था। लिहाजा इस मामले में उन्होंने कोर्ट में बाबरनामा और आइन-ए-अकबरी का संदर्भ दिया है, जिनसे साफ होता है कि वहां हरिहर मंदिर था। हिंदू पक्ष का कहना है कि मंदिर पृथ्वीराज चौहान के शासन से पहले बना था, जबकि मस्जिद मुगलकाल में मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। लिहाजा, महंत ऋषि राज गिरि महाराज आदि ने 19 नवंबर को सिविल कोर्ट में याचिका दायर कर सर्वे की मांग की थी। इस मामले में सिविल जज के कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन मुख्य याचिकाकर्ता हैं। चूंकि चंदौसी स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य कुमार सिंह की अदालत में वाद दाखिल किया था। इसलिए कोर्ट ने इसी याचिका पर 7 दिन में सर्वे रिपोर्ट मांगी है, जिसे 29 नवंबर को जमा करना है। कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव के नेतृत्व में टीम ने 19 नवंबर की शाम को ही सर्वे की शुरुआत कर दी थी। रविवार को टीम सर्वे की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए दोबारा मस्जिद पहुंची थी। मसलन, कोर्ट से सर्वेक्षण का आदेश जारी होने के बाद मंगलवार को जब पहली बार सर्वे हुआ, तब से ही मुस्लिम समुदाय में असंतोष फैलने लगा और उस दिन भी विरोध हुआ था। क्योंकि मुस्लिम पक्ष मान रहा है कि इस प्रक्रिया में जल्दबाजी की गई, उनको पर्याप्त समय या अवसर नहीं दिया गया।

शिक्षा, सेहत, पर्यावरण पर देना होगा ध्यान

हाल में संपन्न महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में पूरे देश ने रुचि ली। चुनाव लोकतंत्र का आधार स्तंभ हैं। उनकी प्रक्रिया, शुचिता और परिणाम पर विश्वास भी उतना ही आवश्यक है। चुनाव परिणामों पर चर्चा हर प्रजातांत्रिक देश के लोगों का ध्यान आकर्षित करे तो इसे लोकतंत्र व्यवस्था का अनिवार्य अंग मानते हुए सभी को संतुष्ट होना चाहिए। परिणाम के पश्चात जीतने वाले और न जीत पाने वाले के कार्यक्षेत्र और उत्तरदायित्व स्वत: ही निर्धारित हो जाते हैं। दोनों ही पक्षों को जनहित में अपने को समर्पित कर देना ही लोकतांत्रिक अपेक्षा है। इसमें पारस्परिक सहयोग की कोई मनाही नहीं है। विजेता को जन-अपेक्षाओं को पूरा कर सकने की क्षमता के उपयोग में लग जाना चाहिए और हारे हुए को जन-सेवा में अपने को समर्पित करने के अवसर का लाभ उठाना चाहिए। चुनाव-चर्चा अब देश और संचार माध्यमों का प्रिय शगल बन गया है। देश के संचार माध्यम दलगत राजनीति से जुड़े हुए नेताओं, उनके वक्तव्यों और उसके विश्लेषण पर बहुत समय और स्थान को दे रहे हैं। परिणामस्वरूप जिन समस्याओं और उनके त्वरित समाधान पर राष्ट्रव्यापी चर्चा होनी चाहिए, वह पीछे छूट जा रही है। महाराष्ट्र के चुनावों के समय वहां किसानों की आत्महत्याओं और सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के संबंध में कहीं कोई समाचार पढ़ने-सुनने को नहीं मिला। कोई प्रत्याशी या दल भी समयबद्ध सीमा में उनकी स्थिति सुधारने का संकल्प लेता नहीं दिखा। चुनावों के दौरान तो ऐसा लगा कि महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या जैसी कोई समस्या है ही नहीं। किसानों और उनकी समस्याओं को लेकर केवल किसान आंदोलन के दौरान संचार माध्यम स्थान और समय दे रहे थे। हालांकि उसमें भी उनकी समस्याओं का विश्लेषण कम और नेताओं के आरोप-प्रत्यारोप ही अधिक प्राथमिकता पाते रहे। ऐसे आंदोलन जब समाप्त हो जाते हैं, तब लगता है कि अब उस समस्या का समाधान हो गया है। इस पर जिस गहन विचार विमर्श की आवश्यकता है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अनेक वर्षों से किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या को लेकर आंकड़े देश के सामने कभी-कभी आ जाते हैं, लेकिन वे राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी चर्चा का विषय नहीं बनते, जो किसी समाधान तक पहुंच सके। इसका समाधान दलगत राजनीति से ऊपर उठकर करना उनका संवैधानिक ही नहीं,

बल्कि नैतिक और मानवीय उत्तरदायित्व है। कितने नव-निर्वाचित विधायक यह प्रण ले सकते हैं कि अगले तीन वर्षों में वे जीजान लगाकर किसानों की आत्माहत्याओं को जनित करने वाली स्थितियों को समाप्त कर देंगे? सामान्य नागरिक की यह सहज जिज्ञासा है कि क्या इस देश के किसानों की आत्महत्या को रोक सकने लायक नीतियां और योजनाएं बनाने के लिए देश का राजनीतिक नेतृत्व एवं वरिष्ठ अधिकारी अक्षम हैं? क्या देश में ऐसे अध्ययनशील विद्वानों की कमी है, जो इससे जुड़ी समस्याओं को गहराई से समझते हों और उनके व्याहारिक समाधान निकाल सकने की क्षमता रखते हों? देश में लगभग हर प्रांत में कृषि विश्वविद्यालय हैं। इंडियन काउंसिल आफ एग्रीकल्चर रिसर्च नाम की एक प्रतिष्ठित संस्था भी है, जिसकी अनेक शाखाएं हैं और जिसके योगदान की सराहना देश-विदेश में की जाती है। भारत के विज्ञानियों और इस संस्था ने अनाज की कमी से जूझ रहे देश को कुछ दशकों के प्रयास के पश्चात उसका निर्यातक बना दिया। क्या इस संस्था को यह उत्तरदायित्व नहीं दिया जा सकता था कि वह ऐसी नीतियां बनाए, जिससे किसानों की समस्या सुलझ सके और बड़ी संख्या में हो रही आत्महत्याएं बंद हो सकें? देश में ऐसा कौन व्यक्ति है, जो किसानों के योगदान की प्राथमिकता को न जानता हो। शायद ही कोई हो, जो किसान की कठिनाइयों से पूरी तरह अपरिचित हो। देश में किसानों की आत्महत्या पर कष्ट हर उस व्यक्ति को होना चाहिए, जिसकी संवेदनाएं सजग हैं, जो यह आज भी याद करता है कि महात्मा गांधी चाहते थे कि हर व्यक्ति जो भी प्रकल्प हाथ में ले या नया रोजगार प्रारंभ करे या किसी परियोजना में हिस्सेदारी करे, उसे सबसे पहले यह विचार करना चाहिए कि इससे पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में क्या कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ सकेगा या नहीं।

इस स्तर की संवदेनशीलता हमारे चयनित जनप्रतिनिधियों और संवैधानिक पदों पर बैठ कर विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने वाले और योजनाएं बनाने वाले व्यक्तियों में जागृत होनी चाहिए। देश की समस्याओं के समाधान के प्रति अनेक जनप्रतिनिधियों में संवेदना और इच्छाशक्ति की कमी का दूसरा उदाहरण शिक्षा क्षेत्र की लगातार बढ़ रही उस अस्वीकार्य स्थिति का है, जिसके प्रति नीति निर्माताओं और इन्हें लागू करने वालों के अंदर एक उदासीनता की भावना निर्मित हो चुकी है। ऐसा कोई दल नहीं है, जो संविधान के प्रति संपूर्ण समर्पण की दुहाई दिन प्रतिदिन न देता हो। ऐसा भी कोई नहीं है, जो डा. आंबेडकर के योगदान की सराहना न करता हो। संविधान के आत्मा के प्रति प्रतिबद्धता में सबसे पहले तो वही वर्ग आता है, जो सदियों से शिक्षा की रोशनी से दूर है, जिसका सामाजिक और सांस्कृति आधार कमजोर है। क्या हर उस बच्चे को उचित शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, जो समाज के इस प्रकार के वर्गों से आता है? देश में सरकारी और निजी स्कूलों के मध्य एक ऐसा विभाजन लगातार बढ़ रहा है, जो राष्ट्रीय स्तर पर गहन चिंता का विषय होना चाहिए।

यूपी बीजेपी को मिलेगा ऐसा अध्यक्ष जो साधेगा सामाजिक समीकरण

उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नये अध्यक्ष की तलाश काफी तेजी से चल रही है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने संगठन के जरिए एक मजबूत सोशल इंजीनियरिंग बनाने की रणनीति पर काम कर रही है,जिसके चलते संभावना व्यक्त की जा रही है आलाकमान इस बार नये प्रदेश अध्यक्ष के पद पर किसी ऐसे नेता को बैठा सकता है जो दलित या महिला समाज से ताल्लुक रखता हो, इसके जरिये बीजेपी की सभी जातियों और वर्गों के बीच बैलेंस बनाने की है। गत दिवस 27 नवंबर को हुई बैठक में राष्ट्रीय सह चुनाव अधिकारी नरेश बंसल ने कहा कि संगठन में सभी जातियों और वर्गों को उचित स्थान दिया मिलेगा। बैठक में यह भी कहा गया कि महिलाओं और दलितों की सहभागिता बढ़ाने पर बीजेपी खास ध्यान देगी ताकि राजनीति में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। बैठक में साफ तौर पर कहा गया है कि बीजेपी कोई परिवारवादी पार्टी नहीं, बल्कि परिवार भाव से चलने वाली पार्टी है. बीजेपी की दलित और महिलाओं को संगठन में जगह देकर भविष्य की राजनीति को साधने की स्ट्रैटेजी है। ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को नए साल में प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। वहीं 16 से 30 दिसंबर के बीच जिलाध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े की संगठनात्मक चुनाव में पर्यवेक्षक बनाया गया है। तावडे एक दिसंबर को चुनाव के संबंध में आयोजित बैठक में हिस्सा लेंगे। इससे पहले 28 से 2 दिसंबर तक जिला स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। चुनाव के लिए प्रत्येक तीन जिलों के लिए एक केंद्रीय पर्यवेक्षक बनेगा। वहीं 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक मंडल अध्यक्षों का चयन होगा। 6 दिसंबर को डॉ. भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि बूथ स्तर पर मनाई जाएगी। वहीं 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाएगी। तत्पश्चात 27 दिसंबर को पार्टी बाल शहीद दिवस मनाएगी। बता दें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल पूरा हो चुका है और उनकी जगह पर नए अध्यक्ष का चुनाव होना है। इससे पहले बीजेपी सभी बूथ कमेटी का गठन करने में लगी है, जिसके लिए 30 नवंबर की टाइम लाइन रखी गई है। यूपी में करीब 1.62 लाख से ज्यादा बूथों पर गठन होना है, जिसमें 35 फीसदी बूथों पर कमेटियां गठित हो चुकी हैं, जबकि बाकी बची बूथ कमेटियों का गठन 30 नवंबर तक पूरा कर लिया जाए। इसके बाद फिर एक से 15 दिसंबर के बीच मंडल अध्यक्ष और 16 से 30 दिसंबर तक जिला अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया चलेगी. इससे पहले जिला स्तर पर बीजेपी कार्यशालाएं आयोजित करेगी। उधर, बीजेपी ने संगठन में युवाओं को अहमियत देने के उम्र लिमिट तय कर दी है। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल ने बताया कि मंडल अध्यक्ष की आयु 35 से 45 वर्ष के बीच और जिलाध्यक्ष की आयु 45 से 60 वर्ष के बीच होगी। ऐसे में साफ है कि बीजेपी 45 साल से ऊपर के उम्र वालों को मंडल अध्यक्ष नहीं बनाएगी और न ही 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को जिला अध्यक्ष की कमान सौंपेगी। बीजेपी ने तय किया है कि दो बार मंडल अध्यक्ष रहने वाले नेताओं को तीसरी बार मंडल अध्यक्ष नहीं बनाएगी। इसके अलावा बीजेपी ने जिला अध्यक्ष के लिए तय किया है कि जिला अध्यक्ष की कमान उसे ही मिलेगी, जो 7 से 8 साल तक संगठन में काम करने का अनुभव होगा। इसके अलावा मौजूदा समय में बीजेपी के संगठन में किसी पद पर होना हो, उसे ही पार्टी जिले का अध्यक्ष बनाएगी। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को नए साल में प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। वहीं 16 से 30 दिसंबर के बीच जिलाध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े की संगठनात्मक चुनाव में पर्यवेक्षक बनाया गया है।

ये है वो इकलौते पाकिस्तानी एक्टर जिसने जीता हिंदुस्तानी अवॉर्ड

मुंबई। पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान आज न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हिन्दुस्तान सिनेमा का भी एक जाना-माना चेहरा है। फवाद ने फिल्म 'खूबसूरत' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस मूवी में उनके साथ एक्ट्रेस सोनम कपूर लीड रोल में नजर आईं थी। ये फिल्म 19 सितंबर, 2014 को रिलीज हुई थी। इसके अलावा फवाद 'कपूर एंड सन्स', और 'ऐ दिल है मुश्किल' जैसी हिंदी फिल्मों के लिए जानते हैं। फवाद खान को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें एक फिल्मफेयर पुरस्कार है। ये अवॉर्ड उन्हें बॉलीवुड फिल्म 'खूबसूरत' में बेस्ट मेल डेब्यू के लिए मिला था। फवाद इस अवॉर्ड को जीतने वाले पहले और इकलौते पाकिस्तानी एक्टर बने।

लाइफ Style

सारा

घूमना-फिरना है बहुत पसंद

सारा अली खान को घूमना-फिरना बहुत पसंद है और उन्हें अक्सर दुनिया की सैर करते हुए देखा जाता है। हाल ही में, उन्होंने एक बार फिर प्रशंसकों को वेकेशन गोल दिए हैं। सारा ने जोधपुर, राजस्थान की अपने सफर से कई शानदार तस्वीरें साझा कीं। सारा का कैज़ुअल लुक प्रशंसकों को बेहद पसंद आया।

सारा अली खान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें हम उन्हें शहर के वास्तुशिल्प चमत्कारों और परिदृश्यों की खोज करते हुए देख सकते हैं। राजसी मेहरानगढ़ किले से लेकर रंगीन स्थानीय बाजारों तक, सारा ने खुद को जोधपुर के शाही अंदाज में सराबोर कर दिया। सारा ने बेज रंग की फ्लेयर्ड पैंट और नीले रंग का टॉप चुना। इस दौरान सारा ने अपने मिनिमल मेकअप और प्यारी मुस्कान से सभी का दिल जीत लिया। काम की बात करें तो सारा अली खान को आखिरी बार कन्नन अय्यर द्वारा निर्देशित प्राइम वीडियो फिल्म ऐ वतन मेरे वतन में देखा गया था। अभय वर्मा और स्पर्श श्रीवास्तव की सह-अभिनीत इस फिल्म में सारा ने एक शानदार देशभक्ति की भूमिका निभाई थी। इसके बाद, वह आदित्य रॉय कपूर के साथ अनुराग बसु की मेट्रो इन डिनो में नजर आएंगी।

कलाकारों की टुकड़ी में पंकज त्रिपाठी, नीना गुप्ता और अनुपम खेर जैसे दिग्गज शामिल हैं। इसके अलावा, सारा फिलहाल आयुष्मान खुराना के साथ धर्मा प्रोडक्शन की एक अनाम फिल्म पर काम कर रही हैं। आकाश कौशिक द्वारा निर्देशित यह फिल्म कथित तौर पर एक हल्की-फुल्की रोमांटिक ड्रामा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सारा पंचायत फेम दीपक मिश्रा द्वारा निर्देशित ग्रामीण लोक-थीम वाली फिल्म के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ काम कर सकती हैं।

हॉलीवुड मसाला

इनकम से ज्यादा हो गए हैं खर्चे!

लॉस एंजिल्स। पॉप आइकॉन जस्टिन बीबर की तगड़ी फैन फॉलोइंग है। भारत में भी उनके बेशुमार फैंस हैं। वो पिछले लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं, जिस वजह से उन्होंने अपने कई टूर भी कैंसिल कर दिए थे। लेकिन, अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स बता रही हैं कि वो खराब सेहत के बावजूद टूर शुरू करेंगे। इसकी वजह ये है कि वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं! जस्टिन के खर्चे, उनकी इनकम से ज्यादा हो गए हैं। ऐसे में खराब हेल्थ के बावजूद उन्हें मजबूरन म्यूजिकल टूर करना पड़ेगा।

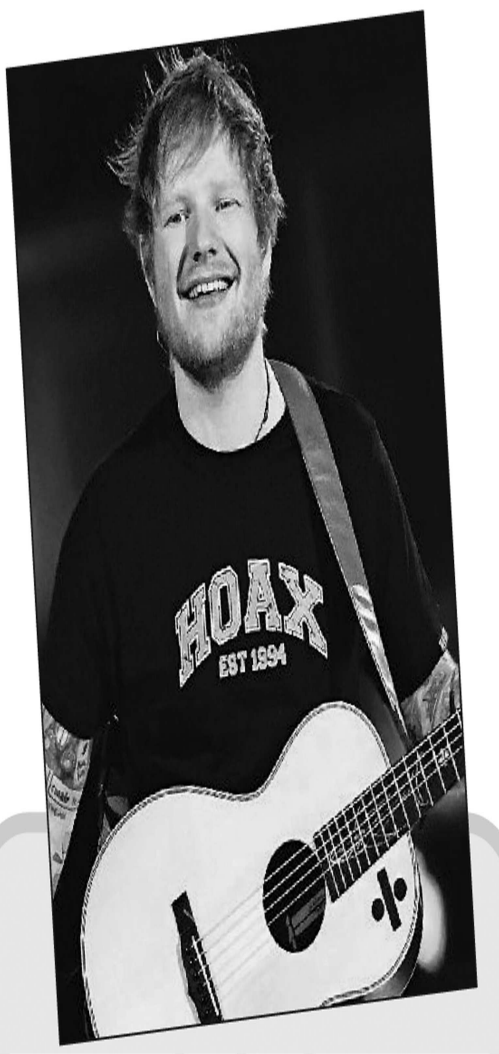

6 शहरों में होगा एड शीरन का कॉन्सर्ट

लॉस एंजिल्स। ब्रिटिश म्यूजिशियन और पॉप स्टार एड शीरन ने साल 2025 में भारत में अपने टूर की घोषणा है। इसमें वे छह शहरों को शामिल करने जा रहे हैं। ये घोषणा मुंबई में उनके शो की टिकट के खत्म होने के बाद ही कर दी थी, कि वे जल्द भारत में वापस आएंगे। शीरन जिन शहरों में कॉन्सर्ट करने वाले हैं, वे पुणे, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरू, शिलांग और चेन्नई हैं। शुरुआत 30 जनवरी को पुणे के यश लॉन्स से होगी, उसके बाद 2 फरवरी को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी, 5 फरवरी को चेन्नई के वाईएमसीए ग्राउंड और 8 फरवरी को बेंगलुरु के नाइस ग्राउंड्स में होगी। इसके बाद 12 फरवरी को शिलांग के जेएन स्टेडियम में प्रस्तुति देंगे और 15 फरवरी को दिल्ली एनसीआर के लीजर वैली ग्राउंड में समापन करेंगे।

'ऐतराज' के सीक्वल से हुई बाहर

नई दिल्ली। सुभाष घई ने कुछ दिन पहले ही निर्देशक अमित राय के साथ 'ऐतराज 2' लाने की जानकारी दी थी। साल 2004 की फिल्म 'ऐतराज' में अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा और करीना कपूर खान लीड रोल में नजर आए थे। फैंस एक्साइटेड थे कि इस बार भी प्रियंका नजर आएंगी या नहीं। लेकिन. जाने माने डायरेक्टर सुभाष घई ने खुलासा किया है कि प्रियंका फिल्म का हिस्सा नहीं हैं। इस फिल्म के निर्माता सुभाष घई हैं। खुद उन्होंने ही ये पुष्टि की है कि 'ऐतराज 2' पर काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि 'ओएमजी 2' के निर्देशक अमित राय के पास इस फिल्म के सीक्वल के लिए एक शानदार सक्रिप्ट तैयार है। लेकिन ,प्रियंका चोपड़ा 'ऐतराज 2' में नजर नहीं आएंगी, यह निर्माता ने कन्फर्म किया है। वहीं, 2004 में रिलीज हुई 'ऐतराज' में अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा और करीना कपूर खान ने अपने काम से दर्शकों का दिल जीता था।

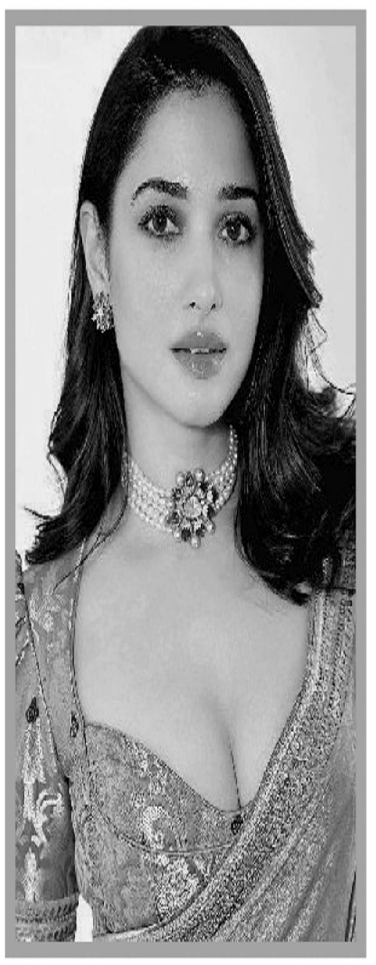

नहीं करना चाहती थीं 'आज की रात' गाना

मुंबई। तमन्ना भाटिया ने साल 2024 में दो सुपरहिट आइटम सॉन्ग दिए हैं। एक रजनीकांत की फिल्म 'जेलर' का 'कावाला' था और दूसरा 'स्त्री 2' का 'आज की रात' था। वहीं अब उनकी फिल्म 'सिकंदर का मुकदर' नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। ऐसे में तमन्ना इस फिल्म का जमकर प्रमोशन कर रही हैं। तमन्ना ने इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान बताया कि वह 'आज की रात' नहीं करना चाहती थीं। उन्होंने इसकी वजह भी बताई। इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने 'स्त्री 2' के गाने 'आज की रात' के लिए 'हां' बोलने में काफी वक्त लगाया था। 'मुझे यह डिसाइड करने में समय लगा कि मुझे 'आज की रात' करना चाहिए या नहीं, क्योंकि तभी मेरा एक गाना (कावाला) रिलीज हुआ था।' सच कहूं तो, मुझे वाकई लगा कि मैंने 'कावाला' में अपना बेस्ट नहीं दिया। मुझे लगा कि मैं और बेहतर कर सकती थी।

के2 ज़ेनॉक्स राजस्थान में अपनी बाजार उपस्थिति को करेगी मजबूत सेल्स में 20% वृद्धि का रखा लक्ष्य

कार्यालय संवाददाता, नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत की सबसे युवा और तेज़ी से बढ़ती टीएमटी बार (द इंटेलीजेंट स्टील) विनिर्माता कंपनी के2 ज़ेनॉक्स राजस्थान में अपनी विस्तार नीति पर तेज़ी से आगे बढ़ रही है। क्षेत्र में अपने इस्पात उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, कंपनी ने अगले एक वर्ष के भीतर अपनी टीएमटी बार उत्पादन क्षमता को 20% तक बढ़ाने की योजना बनाई है।राजस्थान में कंपनी के पास पहले से ही डीलरों और वितरकों का एक मज़बूत नेटवर्क है। के2 ज़ेनॉक्स अपने मिस्त्री मीट, निर्माण के शूरवीर, बिल्डर्स मीट जैसे प्रोग्राम के माध्यम से अपने नेटवर्क का और अधिक विस्तार करेगी। यह रणनीतिक वृद्धि कंपनी की बाजार उपस्थिति को बढ़ाएगी और बिक्री को लगभग 20% तक बढ़ाएगी।के2 ज़ेनॉक्स के निदेशक श्री सुनील अग्रवाल ने कहा, के2 ज़ेनॉक्स एक प्रीमियम उत्पाद है जिसे आधुनिक निर्माण आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए तैयार किया गया है। इसके उत्पादन ने पहले ही देश भर के कई बाजारों में अपनी महत्वपूर्ण पैठ बना ली है और आगे यह नए बाजारों में विस्तार के लिए अग्रसर है। राजस्थान अभूतपूर्व विकास के अवसरों और तेज गति से बुनियादी ढांचे के विकास के साथ आगे बढ़ रहा है और यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है। के2 ज़ेनॉक्स, टीएमटी बार एक प्रीमियम ब्रांड है जो ऐसा अनूठा रिब डिजाइन पेश करता है जो हेक्सागोनल पैटर्न में कॉन्क्रीट के साथ मजबूती से जुड़ जाता है और किसी भी ढांचे के लिए एक पुख्ता बुनियाद व क्वालिटी सुनिश्चित करता है।

भारत का रत्न और आभूषण उद्योग अपना रहा है डायमंड और लैब-ग्रोउन डायमंड्स के लिए एफटीसी गाइडलाइंस

कार्यालय संवाददाता, नई दिल्ली (एजेंसी)। रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, भारतीय रत्न तथा आभूषण उद्योगजगत की शीर्ष निकाय, ने अमेरिका के फेडरल ट्रेड कमीशन (FTC) द्वारा डायमंड्स के लिए निर्धारित नई परिभाषा, नामकरण और दिशानिर्देशों को अपनाया है। स्रञ्जष्ट की अद्यतन गाइडलाइंस डायमंड्स (हीरों) की स्पष्ट और मानकीकृत परिभाषा प्रदान करती हैं और लैब-ग्रोउन डायमंड्स के लिए विशिष्ट शब्दावली सुनिश्चित करती हैं, जिससे उद्योग और उपभोक्ताओं दोनों के लिए पारदर्शिता बनी रहती है।GJEPC के सदस्य डायमंड की नई परिभाषा का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और सभी अन्य रत्न एवं आभूषण व्यापार संगठनों और खुदरा विक्रेताओं से भी ऐसा करने का अनुरोध करेंगे। इसके अतिरिक्त, GJEPC सरकार के साथ परामर्श की प्रक्रिया का नेतृत्व कर रहा है और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को यह नई परिभाषा देश के उपभोक्ता कानूनों के अनुरूप बनाने के लिए प्रस्तुतियां दी हैं।यह कदम उपभोक्ताओं को सूचित निर्णय लेने, भ्रम की स्थिति समाप्त करने और डायमंड की प्रामाणिकता के बारे में किसी भी भ्रामक प्रभाव को रोकने में सक्षम बनाएगा। GJEPC की सिफारिश के बाद, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने डायमंड सेक्टर में उपभोक्ता संरक्षण पर हितधारकों के साथ परामर्श सत्र आयोजित किया है।

इसके साथ ही, CCPA ने डायमंड की शब्दावली की समीक्षा करने और इसी तरह के भारतीय मानक तैयार करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक और लैब-ग्रोउन डायमंड्स (LGD) दोनों उद्योगों की सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करना है। GJEPC के अध्यक्ष, विपुल शाह ने कहा÷चूंकि भारत के रत्न और आभूषण व्यापार ने डायमंड की नई परिभाषा को सर्वसम्मति से स्वीकार किया है, हम भारतीय सरकार और मंत्रालयों से अनुरोध करते हैं कि वे इसे देश के मौजूदा उपभोक्ता कानूनों के अनुरूप स्वीकार करें, अपनाएं और अनुकूलित करें। यह पहल उपभोक्ता हित में है, उनके अधिकारों की रक्षा करती है और गलत सूचनाओं से बचाव करती है। स्रञ्जष्ट की नई परिभाषा तकनीकी प्रगति को दर्शाती है और हीरे के विपणन में स्पष्टता सुनिश्चित करती है, जिससे खदान से निकाले गए और लैब-ग्रोउन डायमंड्स दोनों के लिए समान मानक लागू होते हैं।

उन्होंने आगे कहा- "GJEPC भारतीय व्यापार को शिक्षित करने की प्रक्रिया शुरू करेगा ताकि समान स्तर पर व्यापार सुनिश्चित हो और अनुपालन किया जा सके। यह सुनिश्चित करेगा कि व्यापार मूल्य श्रृंखला के सभी प्रमुख हितधारक उपभोक्ताओं और उपभोक्ता निकायों को मार्गदर्शन, परामर्श और सलाह देने के लिए जिम्मेदार और सशक्त हों।

यह भारत के गौरवशाली रत्न और आभूषण निर्यात के लिए एक नया अध्याय खोलेगा और वैश्विक खरीदारों और निर्यात गंतव्यों में विश्वास भरेगा। जीजेईपीसी सरकार के साथ परामर्श का नेतृत्व कर रही है क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में, उपभोक्ता की समझ यह है कि बिना उपसर्ग के डायमंड का तात्पर्य नेचरल (प्राकृतिक) है, लेकिन मौजूदा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून विशेष रूप से यह नहीं बताता है।

जीजेईपीसी ने सरकार से दोषों, कमियों और अनुचित बिजनेस प्रैक्टिस के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए नई परिभाषा को मौजूदा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुरूप करने का आग्रह किया है।

केप्री ग्लोबल ने गोल्ड लोन भुगतान और सहायता के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट की शुरुआत की

नई दिल्ली (एजेंसी)। एक प्रमुख गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, केप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (केप्री लोन) ने अपने ग्राहकों के लिए गोल्ड लोन अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक AI-सक्षम व्हाट्सएप चैटबॉट की शुरुआत की है। यह इनोवेटिव टूल सुरक्षित भुगतान सुविधाओं को एकीकृत करता है, जिससे उपयोगकर्ता व्हाट्सएप के माध्यम से अपने गोल्ड लोन खातों का प्रबंधन और भुगतान आसानी से कर सकते हैं, यह सुविधा ग्राहकों को शाखा में जाने की आवश्यकता को समाप्त करते हुए सुविधा और दक्षता को प्राथमिकता देती है।

सक्रिय लोन धारकों के लिए गोल्ड लोन सेवाओं को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया यह चैटबॉट कई सुविधाएँ प्रदान करता है, जिनमें व्यक्तिगत लोन स्टेटमेंट्स, फोरक्लोज़र वैल्यू, ब्याज बकाया, और गिरवी रखे गए सोने के डॉक्यूमेंट का विवरण शामिल है–यह सब एक ही उपयोगकर्ता-अनुकूल प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है। यह चैटबॉट 24×7 उपलब्ध है और रियल टाइम में सहायता और व्यक्तिगत समर्थन प्रदान करता है, जो गोल्ड लोन ग्राहकों की अनूठी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

इन ग्राहकों में 60त्न से अधिक के पास एक से अधिक खाते हैं। वर्तमान में यह सेवा अंग्रेजी में उपलब्ध है, लेकिन केप्री लोन जल्द ही इसे कई अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में इसे शुरू करने की योजना बना रहा है।लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए केप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड के गोल्ड लोन बिजनेस हेड, रविश गुप्ता ने कहा, व्हाट्सएप चैटबॉट हमारे डिजिटल सफर में एक और परिवर्तनकारी कदम है, जिसे गोल्ड लोन ग्राहकों को सहज, सुलभ और सुरक्षित लोन प्रबंधन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल और GIZ इंडिया ने ए रोडमैप फॉर सर्कुलर टेक्सटाइल्स इन इंडिया को लॉन्च किया

कार्यालय संवाददाता, नई दिल्ली (एजेंसी)। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड ने डॉयचे गेसेलशाफ्ट फर इंटरनेशनेल जुसामेनारबीट के साथ सहभागिता करके, वाराणसी में आयोजित संकल्प भारत समिट 2024 के दौरान, भारतीय कपड़ा एवं परिधान उद्योग के लिए अपनी तरह के पहले सर्क्युलरिटी दिशा-निर्देशों को बड़े गर्व के साथ लॉन्च करने का ऐलान किया है। इस समारोह में उद्योग जगत के धुरंधरों, सरकारी अधिकारियों और सस्टेनेबिलिटी के विशेषज्ञों सहित कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया, और भारतीय कपड़ा एवं परिधान क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की अहमियत पर रोशनी डाली। यह परियोजना एक तीन-वर्षीय परिवर्तनकारी साझेदारी के उरूज पर पहुँचने की निशानी है। सर्क्युलर अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों, नवाचार और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करके भारतीय कपड़ा क्षेत्र को नई शक्ल देना इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। स्टिचिंग द सर्कल ए रोडमैप फॉर सर्कुलर टेक्सटाइल्स एंड अपैरल इन इंडिया÷ शीर्षक से जारी ये दिशा-निर्देश एक विस्तृत गाइड है, जिसे रेखाकार कपड़ा कारोबार को सर्कुलर अर्थव्यवस्था वाले मॉडल में बदलने के इरादे से डिज़ाइन किया गया है। इसमें एबीएफआरएल और त्रढ्ढं की सहभागिता वाली यात्रा के दौरान उठाए गए कई कदम शामिल हैं। इन पहलों का साझा लक्ष्य यह है कि कपड़े की मूल्य श्रृंखला में सस्टेनिबिलिटी को आगे बढ़ाया जाए, अपशिष्ट को कम किया जाए और संसाधनों की कार्यदक्षता को बढ़ावा दिया जाए। एबीएफआरएल और GIZ के बीच इस दृष्टिकोण के साथ साझेदारी शुरू हुई थी

कि कपड़ा उद्योग द्वारा उत्पन्न होने वाली पर्यावरण-संबंधी गंभीर चुनौतियों का समाधान निकाला जाए। पिछले तीन वर्षों में, इस सहभागिता ने भारत के टेक्सटाइल सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से कई असरदार पहलों का नेतृत्व किया है। इन पहलों में सर्कुलरिटी की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए एक व्यापक बेसलाइन सर्वेक्षण, स्थायी समाधानों को बढ़ावा देने के लिए सर्कुलरिटी इनोवेशन चैलेंज 2023 और कपड़ा मूल्य श्रृंखला में हितधारकों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम- ÷डिकोडिंग सर्कुलरिटी टुगेदर÷ शामिल हैं। एबीएफआरएल और त्रढ्ढं ने कपड़ा आपूर्ति श्रृंखला के साथ सर्कुलर समाधानों को एकीकृत करने के लिए कुछ पायलट प्रोजेक्ट भी चलाए, जिन्हें जागरूकता बढ़ाने और कदम उठाने को प्रेरित करने वाले एक दिलकश नैरेटिव के जरिए दर्ज़ किया गया।

नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार : मुख्यमंत्री

कार्यालय संवाददाता, जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार शहरी बुनियादी ढ़ांचे को विश्व स्तरीय बनाने एवं जनसुविधाओं को सशक्तए समावेशी बनाने की प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को दी जा रही सेवाओं के स्तर को बेहतर बनाया जाए तथा नगरीय विकास के लिए नवीनतम तकनीकों का प्रयोग किया जाएए ताकि शहरी विकास के नए आयाम स्थापित हो सके। मुख्यमंत्री शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित नगरीय विकास विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बजट में विभागीय घोषणाओं की समीक्षा कर उनकी कार्यप्रगति की जानकारी ली तथा उन्हें शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन की अधिक जरूरत वाले स्थानों पर संसाधनों का पहले प्रयोग किया जाएए ताकि जनता को शीघ्र राहत मिल सके।

जयपुर को ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए बनाएं प्रभावी कार्ययोजना : शर्मा ने कहा कि बढ़ती आबादी के चलते जयपुर में यातायात भार लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में क्षेत्र का ट्रेफिक प्रबंधन बेहद जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को ट्रेफिक जाम से निजात दिलाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने जयपुर कलेक्ट्रेट सर्किल एवं गांधीनगर मोड़ पर बढ़ रहे यातायात भार के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ट्रेफिक डाइवर्जन के लिए वैकल्पिक मार्गों का भी विकास किया जाए। मुख्यमंत्री ने रिद्धी.सिद्धी फ्लाईओवरए इमलीफाटक

फ्लाईओवर सांगानेर फ्लाईओवर से चैरड़िया पेट्रोल पम्प तक एलिवेटेड रोड़ए सिविल लाइन्स आरओबीए रामबाग गोल्फ क्लब पार्किंग की प्रगति की जानकारी ली तथा इन कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने द्रव्यवती नदी का सौन्दर्यीकरण आईपीडी टावर के निर्माण जयपुर मेट्रो के विस्तार रिंग रोड़ के निर्माण आरओबी आरयूबी सेक्टर रोड़ ऐलिवेटेड रोड़ सहित विभिन्न विकास कार्यों की भी समीक्षा कर आवश्यक दिशा.निर्देश दिए।

हाउसिंग बोर्ड की संपत्तियों का विवरण हो ऑनलाइन : मुख्यमंत्री ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड का मुख्य काम आमजन को किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ऐसे में मण्डल अपनी आवासीय योजनाओं की गति में तेजी लाए। साथ हीए मण्डल की सभी सम्पत्तियों का विवरण ऑनलाइन होए ताकि लोगों को इनकी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि नई आवासीय योजनाओं में गुणवत्ता का ध्यान रखा जाएए साथ ही ऑनलाइन आवेदन तथा ई.नीलामी की प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाया जाए।

रिक्त पदों पर शीघ्र करें भर्ती : शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जयपुर विकास प्राधिकरणए राजस्थान आवासन मण्डलए मुख्य नगर नियोजक सहित नगरीय विकास विभाग के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की जाए। उन्होंने कहा कि नगरीय विकास विभाग द्वारा जल्द से जल्द अपने अभियान्त्रिकी संवर्ग के सेवा नियम बनाए जाएंए जिससे राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से शीघ्र नवीन पदों पर भर्ती की जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन विभागों में लम्बे समय से एक स्थान पर कार्यरत कार्मिकों को बदला जाएए ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

कार्मिकों के लम्बित प्रकरणों का शीघ्र करें निस्तारण : मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की मंशा है कि भ्रष्टाचार में लिप्त कार्मिकों को नहीं बख्शा जाएगा तथा ईमानदार कार्मिक को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग में कार्मिकों से संबंधित सभी लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करे। बैठक में शहरी परिदृश्य एवं नगरीय निकायों की स्थितिए विभागीय महत्वपूर्ण प्रोजेक्टए नवाचारों मास्टर प्लान एवं जोनल डवलपमेंट प्लान की स्थिति सहित विभिन्न विभागीय बिन्दुओं पर चर्चा की गई।

संकटग्रस्त महिलाओं को तत्काल पुलिस सहायता प्रदान करने के लिए पुलिस मुख्यालय का नवाचार

राजकॉप सिटीजन एप में महिला सुरक्षा के लिए मदद चाहिए का फीचर

संकटग्रस्त महिलाओं के हेल्प मांगने पर तत्काल नजदीकी सहायता उपलब्ध होगी, पीड़िता को एप पर मिलेगी पूरी जानकारी

कार्यालय संवाददाता, जयपुर (कासं)। संकटग्रस्त महिलाओं को तत्काल पुलिस सहायता प्रदान करने के लिये राजकॉप सिटीजन एप, वूमन सेफ्टी के तहत नीड हेल्प के जरिये पुलिस सहायता उपलब्ध कराने की योजना पुलिस मुख्यालय द्वारा शुरू की जा रही है। इसके लिए सर्वप्रथम विभिन्न जिला एवं रेंज स्तर पर सुरक्षा सखी, पुलिस मित्रों एवं अन्य जनसम्पर्क के माध्यम से इस एप के प्रयोग सम्बन्धी डेमोस्ट्रेशन दिया जाएगा। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सिविल राइट्स एवं एएचटी श्रीमती मालिनी अग्रवाल ने इस संबंध में सभी पुलिस अधीक्षक व पुलिस उपायुक्त को निर्देश जारी कर अधिकाधिक राजकॉप सिटीजन एप को मोबाईल पर डाउनलोड करने आमजन को डेमोंसट्रेशन के द्वारा प्रेरित करने को लिखा है। जिससे इस योजना का लाभ संकटग्रस्त महिलाओं को मिल सके। एडीजी श्रीमती अग्रवाल ने बताया कि राजकॉप सिटीजन ऐप में महिला सुरक्षा के लिए मदद चाहिए का Feature दिया गया है। जिसमे आपात स्थिति में सहायता व गैर आपात स्थिति में सहायता की दो तरह की सुविधाएं दी गयी है।

आपात स्थिति में सहायता

आपात स्थिति में सहायता के लिए जब भी किसी महिला द्वारा रिक्वेस्ट की जाती है, तो 1090 कन्ट्रोल रूम (जयपुर) को नोटिफिकेशन जाता है। कन्ट्रोल रूम पर कार्यरत पुलिसकर्मी के नोटिफिकेशन स्वीकृत करने पर इसकी सूचना पीड़ित को ऐप पर दिखायी देती है। इसके बाद पीड़ित को कॉल कर समस्या पता की जाती है। अगर पीड़ित फोन नहीं करने का मैसेज रिक्वेस्ट के साथ भेजता है तो ऐसी स्थिति में लोकेशन पर मदद पहुंचाने की कार्यवाही की जाती है। जयपुर कन्ट्रोल रूम ऑपरेटर द्वारा बिना समय गंवाए सम्बन्धित जिले के अभय कमाण्ड सेंटर को सूचना भिजवाई जाती है। जिसके आधार पर पीड़ित की लोकेशन पर उस जिले के सम्बंधित थाने को पहुँच जाती है। थाना पुलिस या नजदीकी वाहन 112 पीड़ित की लोकेशन पर पहुंच मदद पहुंचाता है। वाहन 112 की लोकेशन पीड़ित एप पर ट्रैक वाहन की सहायता से देख सकता है। एप पर हेल्प मांगने के बाद पीड़ित के पास पुलिस की गाड़ी पहुंचने तक की सभी जानकारी ऐप पर दी जाती है। जरूरी सहायत मिलने के बाद पुलिस कर्मी रिक्वेस्ट बन्द कर देता है। मदद प्राप्त हो जाने पर पीड़ित स्वयं भी रिक्वेस्ट बन्द कर सकता है।

गैर - आपातकालीन

मदद चाहिए के Non- Emergency Help पर क्लिक कर किसी महिला द्वारा रिक्वेस्ट की जाती है, तो उस स्थिति में नोटिफिकेशन को कन्ट्रोल रूम का पुलिसकर्मी स्वीकृत कर पीड़ित को कॉल कर समस्या पता करता है। समस्या सुनने के बाद तुरन्त संबंधित थाने को सहायता उपलब्ध कराने के लिए कॉल करता है। परिवाद होने की स्थिति में कन्ट्रोल रूम कर्मचारी परिवाद प्राप्त कर सीसीटीएनएस में इन्द्राज कर सम्बन्धित थाने को वह परिवाद जांच के लिए भेज देता है। जांच के बाद जो भी कार्रवाई होती है थाना पुलिस द्वारा कॉल कर कन्ट्रोल रूम को दी जायेगी। इस सूचना के आधार पर 1090 कंट्रोल रूम रिक्वेस्ट बंद कर देता है।

आरएमएससीएल एमडी ने किया फार्मेसी काउंसिल का निरीक्षण

कार्यालय संवाददाता, जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा चिकित्सा सेवाओं से संबंधित विभिन्न काउंसिल के कामकाज की समीक्षा के निर्देशों की पालना में गुरुवार को आरएमएससीएल की प्रबंध निदेशक श्रीमती नेहा गिरि ने फार्मेसी काउंसिल का निरीक्षण किया और वहां संपादित होने वाले कार्यों का जायजा लिया।

गिरि ने कार्मिकों से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, लंबित आवेदनों एवं काउंसिल की अन्य गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने काउंसिल में कार्यरत कार्मिकों और उनको आवंटित कार्यों के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही, काउंसिल के नियम, प्रक्रियाओं आदि के बारे में समीक्षा की।

निवेशकों के बढ़ते भरोसे पर मूडीज ने वेदांता रिसोर्सेज की रेटिंग में सुधार किया

कार्यालय संवाददाता, नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिका स्थित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज रेटिंग्स ने वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड (वीआरएल) की कॉरपोरेट फैमिली रेटिंग को बी3 से बढ़ाकर बी2 और कंपनी के सीनियर अनसिक्योर्ड बॉन्ड की रेटिंग को सीएए1 से बढ़ाकर बी3 कर दिया है। ऐसा करते हुए मूडीज ने दोनों रेटिंग पर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा है और अपग्रेड के कारणों में से एक के रूप में निवेशकों के बढ़ते भरोसे का हवाला दिया है। अक्टूबर में किए गए अपग्रेड के बाद एक महीने के भीतर मूडीज द्वारा वीआरएल के लिए यह दूसरा अपग्रेड है।मूडीज की वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर क्रेडिट ऑफिसर निधि ध्रुव ने कहा, ÷रेटिंग अपग्रेड वीआरएल के देनदारियों संबंधी सफल प्रबंधन के बाद हुआ है, जिसमें कंपनी ने सितंबर 2024 के बाद से अपने दूसरे बॉन्ड जारी करने में 800 मिलियन डॉलर जुटाए हैं।उन्होंने कहा, ÷बॉन्ड जारी करने से वेदांता की पूंजी बाजारों तक पहुंच मजबूत हुई है और साथ ही कंपनी में निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है।क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने वीआरएल के बड़े पैमाने पर और विविधतापूर्ण कम लागत वाले संचालन पर भी ध्यान दिया है।

दहेज हत्या की आरोपी सास व ननद को 7 7 साल का कारावास

कोटा (कासं)। न्यायालय ने दहेज प्रताड़ना के चलते महिला द्वारा जहर खाकर आत्महत्या कर लेने के मामले में आरोपी सास कमलाबाई पत्नी बाबूलाल व ननद देवकी निवासी गोदल्याहेडी थाना कैथून को दोषी करार देते हुए 7 साल का कारावास की सजा से दंडित किया है। प्रकरण में 24 अक्टूबर 2016 को फरियादी सत्यनारायण ने थाना कैथून में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह इटोडा गांव थाना सदर बूंदी का रहने वाला है।

वे दो भाई व दो बहिन हैं जिसमें से बड़ी बहिन उषा बाई की शादी आज से 3 वर्ष पहले गोदल्याहेडी गांव के गजानन उर्फ लडडूलाल मेहर के साथ की थी, जिसके एक लड़का है,जिसका नाम दीपेश है जिसकी उम्र दो साल है। उसकी बहिन गांव आती थी, तब उनसे कहती थी कि उसे उसकी सास कमलाबाई, ससुर बाबूलाल जी, देवर महावीर, गोलू,ननद देवकी और उसका पति गजानन उर्फ लडडू लाल ये सभी परेशान करते थे।

उसकी बहिन कल उसके दादाजी का देहान्त होने की वजह से तीन दिन में आई थी,जो नहा धोकर चुपचाप वापस अपने ससुराल चली गई थी।

लेकिन दादाजी की मृत्यु के गम की वजह से कुछ कह नहीं पाई, लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था,जैसे वो गंभीर दुख दुविधा में हो, उसे व उसके परिवार को शक है कि इसके साथ गंभीर हादसा हुआ है, ये लोग पूर्व में भी 6 महीने पहले मारपीट कर चुके थे, तब वो 2 महीने उनके पास रही लेकिन लोकलाज की वजह से उन्होंने उसे समझा बुझाकर वापस ससुराल भेज दिया था। आज उसे उसकी बहिन के देवर महावीर ने फोन पर बताया कि तुम्हारी बहिन मर चुकी है, आकर देख लो,ये मुर्दाघर कोटा में है। वह और उसका परिवार सहित कोटा आये जहां उसकी बहिन उषा को मृत अवस्था में देखा जिसके शरीर पर कोई जाहिरा चोट वगैरह भी नजर नहीं आई, इसलिए उसे व उसके परिवार को शक है कि या तो इसे जहर देकर या फिर गला घोंटकर मारा गया है। रिपोर्ट के आधार पुलिस थाना कैथून, में धारा 304 बी भारतीय दण्ड संहिता में मुकदमा दर्ज कर बाद आवश्यक अनुसंधान उक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 304 बी. 34 भा.द.सं. के तहत संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया।

प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से 23 गवाहों के बयान एवं 19 दस्तावेज बतौर सबूत प्रदर्शित करवाए गए।

हादसे की आशंका : 2.93 करोड़ से बनी पटेल नगर पुलिया में 1 साल में ही आई दरारें

4 इंच धंसा स्लैब, भारी वाहनों का गुजरना जारी

कार्यालय संवाददाता, बीकानेर (कासं)। पटेल नगर में 2.93 करोड़ रुपए की लागत से एक साल पहले बना पुलिया निर्माण में ठेकेदार और अधिकारियों की अनदेखी के चलते पुलिया में दरारें पड़ गई हैं। स्लैब 4 इंच धंस चुका है। इसके नीचे से गुजरने वाली सीवर लाइन जगह-जगह टूटने से लगातार पानी बह रहा है। जिससे दीवारें कमजोर हो चुकी हैं। पुलिया के गिरने का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने घटिया निर्माण और प्रशासन की लापरवाही को हादसे के लिए खुला निमंत्रण बताया है। इसके बावजूद प्रशासन ने यहां से भारी वाहनों का आवागमन बंद करने की जहमत नहीं उठाई। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि निर्माण कार्य के दौरान सीवर लाइन और पुलिया दोनों में

घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिसका परिणाम अब सामने आ रहा है। सीवर लाइनें भी जगह-जगह टूट चुकी हैं। बीते दिनों एक ईंटों से भरा ट्रक सीवर लाइन के ऊपर धंस गया था। जिससे पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद से सीवर का गंदा पानी बाइपास कर दूसरी लाइन में छोड़ा जा रहा है। जिम्मेदारी लेने की जगह पर नगर निगम और यूआईटी के अभियंता इस मामले में आमने सामने हैं। सीवर लाइन जाम होना भी समस्या की वजह है और तीन करोड़ के निर्माण के समय पुरानी सीवर लाइन का ध्यान न रखना भी बड़ी अनदेखी है।

कैसे टूटी सीवर लाइन : यह जांच का विषय हो सकता है कि ओवर लोड ट्रक के कारण सीवर लाइन टूटी या टूटी सीवर लाइन में ट्रक धंस गया। अभी सच ये है कि पुल के नीचे से गुजरने वाली सीवर लाइनें भी जगह-जगह टूट चुकी हैं। ये भी लोगों ने देखा है कि ईंटों से भरा ट्रक सीवर लाइन के ऊपर धंस गया था। अब सीवर का गंदा पानी बाइपास कर दूसरी लाइन में छोड़ा जा रहा है, जिससे इलाके में भयंकर बदबू फैल रही है। स्थानीय निवासी रामनिवास चौधरी ने कहा, सीवर लाइन की बदहाली और पुल के क्षतिग्रस्त होने से यहां लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। प्रशासन के अधिकारी स्थिति का जायजा लेने तक नहीं आए हैं। : पुलिया निर्माण के समय ठेकेदार ने मापदंडों की अनदेखी की और अधिकारियों ने इसे नजरअंदाज कर मंजूरी दे दी।

राज्य सड़कों के लिए बड़ी सौगात

प्रदेश की 27 सड़कों के लिए केन्द्र ने 1154.47 करोड़ रूपये की दी मंजूरी

कार्यालय संवाददाता, जयपुर (कासं)। प्रदेश की 27 सड़कों के विकास के लिए केन्द्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 1154.47 करोड़ रूपये की तथा श्रीगंगानगर में रेलवे अण्डर ब्रिज निर्माण के लिए 30 करोड़ रूपये स्वीकृति दी है। इस राशि से राज्य की 748.80 कि.मी की सड़कों का चौड़ाई करण एवं सुदृढीकरण तथा कोटा में कालीसिंध नदी पर हाईलेवल ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के प्रयासों से केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से राज्य सड़कों के विकास के लिए तथा सेतु बंधन योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा यह राशि स्वीकृत की गई है। गौरतलब है कि प्रदेश की विभिन्न सड़कों एवं नवीन वृहद परियोजनाओं के विकास में सहयोग के लिए उप मुख्यमंत्री ने गुरूवार को केन्द्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश के लिए यह महत्वपूर्ण सौगात है,केंद्र सरकार द्वारा 27 राज्य सड़कों के लिए 1154.47 करोड़ रुपये की मंजूरी मिलना, राज्य के बुनियादी ढांचे और विकास को गति देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सड़कों के निर्माण से राजस्थान के कई क्षेत्रों को लाभ होगा। इससे न केवल परिवहन सुगम होगा बल्कि व्यापार, पर्यटन और कृषि क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही बेहतर सड़क नेटवर्क से राज्य में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

इन जिलों मे होगा सड़क निर्माण : प्रदेश के 15 लोकसभा क्षेत्रों के 17 जिलों में इस राशि से वृहद जिला सड़क (एमडीआर) तथा स्टेट हाईवे श्रेणी की 27 सड़क परियोजनाओं का चौड़ाई करण एवं सुदृढीकरण किया जाएगा। इस राशि से अलवर लोकसभा क्षेत्र के अलवर जिले में 24 करोड़ की लागत से 24 कि.मी,खैरथल-तिजारा जिले में 69 करोड़ की लागत से 51 कि.मी, कोटपूतली-बहरोड़ जिले में 49.30 करोड़ की लागत से 28.62 कि.मी, बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के बालोतरा जिले में 57.50 करोड़ की लागत से 49 कि.मी, भीलवाड़ा के शाहपुरा जिले में 74 करोड़ की लागत से 44 कि.मी, बीकानेर जिले में 73.30 करोड़ की लागत से 71.80 कि.मी, चित्तौडगढ के प्रतापगढ जिले में 20 करोड़ की लागत से 17 कि.मी,जयपुर ग्रामीण तथा सीकर लोकसभा क्षेत्र के जयपुर ग्रामीण में 65 करोड़ की लागत से 57.70 कि.मी सड़कों का निर्माण,चौड़ाईकरण एवम सुदृढ़ीकरण करवाया जाएगा। इसी प्रकार जालौर में 65 करोड़ की लागत से 49 कि.मी, झालावाड़ जिले में 149.97 करोड़ की लागत से 81.25 कि.मी,जोधपुर के फलौदी जिले में 55.65 करोड़ की लागत से 53 कि.मी,कोटा के बूंदी जिले में 80 करोड़ की लागत से 33 कि.मी तथा कोटा में 70 करोड़ की लागत से कालीसिंध नदी पर हाईलेवल ब्रिज का निर्माण,पाली के जोधपुर ग्रामीण में 98 करोड़ की लागत से 67 कि.मी,राजसमंद में 70 करोड़ की लागत से 58 कि.मी, टोंक में 58.50 करोड़ की लागत से 25.43 कि.मी तथा उदयपुर में 65.25 करोड़ की लागत से 39 कि.मी राज्य सड़कों का सुदृढीकरण एवं चौड़ाईकरण करवाया जाएगा।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर कार पलटी, पति-पत्नी की मौत

कार्यालय संवाददाता, अलवर (कासं)। दिल्ली-मुंबई सुपर एक्सप्रेस-वे पर शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे कार (वगैनार) पलटकर पुलिया के बीच में फंस गई। हादसे में कार सवार पति-पत्नी की मौत हो गई। वहीं उनकी बहन-बहनोई, भांजा-भांजी और बेटा घायल हो गए। सभी सोनीपत के रहने वाले हैं और मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने जा रहे थे। हादसा अलवर में बडौदामेव के पास का है। घायलों को अलवर जिला हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। वहीं शव बड़ौदामेव सीएचसी में हैं। उनके परिजनों को हादसे की सूचना दी गई है। प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि कार चालक को नींद की झपकी आने पर बैलेंस बिगड़ा और दूसरी कार से टकराकर पलट गई।

बलेनो कार की टक्कर से पलटी वैगनआर: घायल सोनीपत के रहने वाले राजकुमार (38) ने बताया- वह पत्नी पूजा, बेटी दिव्यांशी (6), बेटे रुद्राक्ष

(3) के अलावा अपने साले कमल और साले की पत्नी सिया व उनके बेटे चीकू के साथ मेहंदीपुर बालाजी दर्शन के लिए जा रहे थे। बडौदामेव के पास बलेनो कार से टकराने के बाद हमारी कार पलटते हुए आगे पुलिया के बीच खाली हिस्से में फंस गई।

3 साल पहले हुई थी शादी: कार पलटने पर उसमें सवार कमल और उनकी पत्नी सिया की मौत हो गई। वहीं उनका बेटा, बहन-बहनोई और भांजा-भांजी घायल हो गए। कमल प्राइवेट कंपनी में बतौर सुपरवाइजर काम करते थे। जिनकी 3 साल पहले ही शादी हुई थी। उनके एक बेटा है। जो उनके साथ ही कार में था। कमल का परिवार सोनीपत में तारा नगर में रहता है। उन्हें हादसे की सूचना दे दी गई है।

हादसे में पांच घायल

एबुलेंसकर्मी सचिन कुमार ने बताया- दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर एक्सीडेंट की सूचना पर पहुंचे। कार पुलिया में फंसी हुई थी। सभी को कार से निकालकर बड़ौदामेव सीएचसी लेकर गए। दो जनों की मौत हो गई थी। बाकी पांच घायलों को जिला हॉस्पिटल रैफर किया गया।

साला व पत्नी की मौत, बेटा घायल : कमल और साले की पत्नी सिया सोनीपत में तारा नगर में रहते हैं। कमल प्राइवेट कंपनी में बतौर सुपरवाइजर काम करता है। जिनकी 3 साल पहले ही शादी हुई थी। जिनके एक बेटा है। जो उनके साथ ही था। गंभीर घायल है। जिला अस्पताल में इलाज जारी है।

संत भावनाथ आश्रम में 13 दिसंबर से होगा 21 कुंडीय विष्णु महायज्ञ

कार्यालय संवाददाता, श्रीगंगानगर (कासं)। श्रीगंगानगर रोड कानासर फांटा स्थित संत भावनाथ आश्रम में 13 दिसंबर से शुरू होने वाले 21 कुंडी विष्णु महायज्ञ एवं श्रीमद्भागवत कथा में अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को जोड़ने के लिए आयोजन समिति की ओर से बैनर, फ्लैक्स लगाने और प्रबुद्ध लोगों को घर-घर जाकर आमंत्रण देने की शुरुआत के साथ वहां बैठकों को दौर शुरू हुआ। आयोजन समिति के प्रहलाद ओझा ने बताया कि शहरी क्षेत्र के मुख्य-मुख्य मंदिरों एवं शहर के आस पास के गांव में यज्ञ एवं कथा आयोजन की पूरी जानकारी के बैनर लगाए जाने हैं जिसके तहत सर्वप्रथम गावों से शुरूआत की गई। गांव सोवा, गजरूपदेसर, खारा, हुसंगसर एवं गेरसर के मंदिरों में गुरुवार को बैनर लगाए गए। ओझा ने बताया कि खारा के सरपंच भैरुंसिंह और हुसंगसर के सरपंच शिव प्रजापत सहित कई लोगों को आमंत्रण के समय गांव वालों की तरफ से आयोजन को सफल बनाने के लिए आश्वस्त किया गया।

बेलासर-द्वितीय 33 केवी जीएसएस का किया शुभारम्भ ग्रामीण विकास के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही सरकार : गोदारा

कार्यालय संवाददाता, बीकानेर (कासं)। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने शुक्रवार को रुपेरा और नौरंगदेसर में नवनिर्मित ट्यूबवेल का लोकार्पण किया। श्री गोदारा ने बेलासर-द्वितीय में 33 केवी जीएसएस का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र में ढांचागत विकास के लिए विशेष ध्यान दे रही है। ग्रामीणों को सुचारू विद्युत और पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में सतत रूप से नई स्वीकृतियां जारी की जा रही हैं। ग्राम वासियों को ट्यूबवेल निर्माण की बधाई देते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि रूपेरा और नौरंगदेसर में लंबे समय से ग्रामीणों की मांग को पूरा किया गया है। नया ट्यूबवेल बनने से ग्रामीणों को सुगम पेयजल आपूर्ति हो सकेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में काम किया जा रहा है। ग्रामीणों की मांग के अनुरूप प्राथमिकता से ट्यूबवेल, जीएसएस, सड़कें, स्वास्थ्य केंद्र निर्मित करवाए जा रहे हैं। स्कूलों में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए नए कक्षा कक्ष निर्माण के साथ रिक्त पदों पर स्टाफ की नियुक्ति का कार्य भी प्राथमिकता पर है। उन्होंने कहा कि गत एक वर्ष में डबल इंजन की सरकार ने पूरी क्षमता से आमजन के जीवन स्तर को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। बजट घोषणाओं में जिले के विकास के लिए अभूतपूर्व घोषणाएं की गई हैं। इनके समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक स्तर पर समुचित समन्वय किया जा रहा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि %शिक्षित लूणकरणसर, विकसित लूणकरणसर% की दिशा में संकल्पबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। क्षेत्र की सभी प्राथमिकताओं को चरणबद्ध तरीके से पूर्ण करते हुए क्षेत्र वासियों को सभी आधारभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। इससे पहले ग्रामीणों द्वारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री का स्वागत किया गया। इस अवसर पर सरपंच रामदयाल गोदारा , हेतराम कूकणा, गणपत गोदारा, अखाराम गोदारा, रामनिवास खीचड़, पूर्व सरपंच रामलाल गोदारा, पंचायत समिति सदस्य रवि सारस्वत, उपप्रधान राजकुमार कस्वा, अधिशासी अभियंता नरेश कुमार रेगर सहित ग्रामीण एवं अधिकारी मौजूद रहे।

शनिवार को करेंगे जनसुनवाई : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सुमित गोदारा शनिवार को सादुलगंज स्थित अपने आवास पर आमजन के अभाव अभियोग सुनेंगे। श्री गोदारा प्रात: 9 से दोपहर 3 बजे तक आमजन की समस्याएं सुनेंगे।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक रोहिताश सैन के लिए एम.बी. प्रिन्टर्स, सी-74, सुदर्शनपुरा इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, 22 गोदाम, जयपुर से मुद्रित एवं 48, श्रीराम कॉलोनी, सीतादेवी अस्पताल के सामने, रामनगर सोडाला, जयपुर-302019 से प्रकाशित : मो : 9875033999 सम्पादक: रोहिताश सैन * समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर शहर न्यायालय होगा)